कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/–

त्रि वार्षिक : 250/–

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QSDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा : भाजपा का घोषणा-पत्र जारी

सुशासन एवं विकास का संकल्प 7

रैलियां

नुआपदा, बालंगीर और राउरकेला, ओडिशा 11

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 12

कुरूक्षेत्र और गुड़गांव (हरियाणा) 13

नवादा एवं बक्सर (बिहार) 14

बरेली (उत्तर प्रदेश) 15

कोडरमा (झारखंड) 16

गुमला और चतरा (झारखंड) 18

दिल्ली 20

नांदेड़, अकोला (महाराष्ट्र) 21

लेख

कांग्रेस का कांग्रेस का घोषणा-पत्र : विफल आश्वासनों का स्तुतिगान

– **एम. वेंकैया नायडू** 23

कांग्रेस की बेबसी

– **बलबीर पुंज** 25

कांग्रेस का सेक्युलर विलाप

– **हृदयनारायण दीक्षित** 27

सुनामी बन रही है मोदी की लहर

– **कंचन गुप्ता** 29

सामाजिक समरसता के अग्रदूत

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती

14 अप्रैल

शत-शत नमन!

बोध कथा

सत्य की राह

महात्मा गांधी उन दिनों स्कूल के छात्र थे। उनके स्कूल में खेलकूद अनिवार्य था और यदि कोई विद्यार्थी समय पर मैदान में उपस्थित नहीं होता, तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। गांधीजी को खेलकूद में अधिक रुचि नहीं थी, फिर भी वह निर्धारित समय पर मैदान में पहुंच जाते थे। उन दिनों समय देखने के लिए घरों में घड़ियां कम ही होती थीं। लेकिन, वह अंदाज से हमेशा समय पर ही पहुंचते।

एक दिन गांधीजी अपने पिता की सेवा में लगे हुए थे। उस दिन आसमान में बादल छाए थे इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जब वह स्कूल पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। खेलकूद का समय निकल गया था। गांधीजी ने देखा कि मैदान खाली है तो वह अपनी कक्षा में लौट आए। अगले दिन जब अध्यापक को पता चला कि वह स्कूल आकर भी मैदान में नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने इस बारे में उनसे पूछा।

गांधीजी बोले, 'मैं तो आया था किंतु उस समय वहां पर कोई विद्यार्थी नहीं था।' यह सुनकर अध्यापक बोले, 'तुम देर से क्यों आए? क्या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं था?' गांधीजी बोले, 'मेरे पास घड़ी नहीं थी और कल आसमान में बादल होने की वजह से सही समय का अंदाजा नहीं लग सका।' अध्यापक को लगा कि गांधीजी झूठ बोल रहे हैं इसलिए उन्होंने उन पर दो आने का जुर्माना कर दिया। जुर्माने की बात सुनकर गांधीजी को रोना आ गया।

वह इस बात से आहत थे कि उन्हें उनके शिक्षक ने गलत समझा। उन्होंने सोचा कि जब सच बोलने पर भी सजा मिल सकती है, तो गलती करने के साथ ही झूठ बोलने के दंड का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। यह सोच कर उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि वह आजीवन सत्य बोलेंगे और साथ ही अपने अंदर ऐसा आत्मबल पैदा करेंगे कि उनके द्वारा बोले गए सत्य को सभी सत्य ही समझें, उसके झूठ होने का भ्रम न पालें।

व्यंग्य चित्र

संकलन : रेनू सैनी

(नवभारत टाइम्स से साभार)

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

लक्ष्य अब 300+

इस बार चुनाव कम से कम एक मामले में अद्भुत है- परिणाम एक भी वोट डाले जाने से भी पहले सबको पता है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि श्री नरेन्द्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और केन्द्र में भाजपानीत राजग की सरकार बन रही है। हर दिन 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा गर्म हो रहा है- चारों तरफ कमल ही कमल हैं। लोग उत्साह से लबालब भरे हुए हैं और चुनाव अपने पूरे रंग में है। क्या शहर और क्या दूर-दराज बसे गांव- हर तरफ लोग श्री नरेन्द्र मोदी को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। एक ओर जहां लोग श्री मोदी के 'कांग्रेस मुक्त भारत' के आह्वान पर एकजुट हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने सफाये की बाट जोह रही है।

श्री नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना अब केवल समय की बात रह गई है। यह देश के वातावरण से साफ पता चलता है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद जितने भी सर्वे हुए हैं, इस बात पर पूरी तरह से एकमत हैं कि भाजपानीत राजग ने निर्विवाद रूप से बड़ी बढ़त बना ली है। इंडिया टुडे-सी वोटर जिसने पूर्व में राजग को 212 सीटें दी थी अपने दिसंबर 2013 से जनवरी 2014 के बीच टाईम्स नाऊ-इंडिया टीवी-सी वोटर के अंतर्गत किए सर्वे में राजग को 227 सीटों की भविष्यवाणी की है। अपने फरवरी 2014 के सर्वे में एबीपी न्यूज-निलसन ने राजग को 236 सीटें दी है। फरवरी के अपने सर्वे में सीएनएन-आईबीएन-लोकनीति-सीएसडीएस ने राजग को 212-232 सीटें दी थी जबकि मार्च 2014 के अपने सर्वे में 234-246 सीटें दी हैं। इसी तरह एनडीटीवी-हंसा रिसर्च जिसने पूर्व में राजग को 232 सीटें दी थी मार्च 2014 के अपने सर्वे में इस आंकड़े को सुधार कर 259 सीटें दी है। ये सभी एजेंसियां राजग को 31-36 प्रतिशत तक मतों की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक तरफ जहां ये सर्वे राजग को बड़ी बढ़त दे रहे हैं, रोज नए दल राजग में शामिल हो रहे हैं, और नए मित्र एवं समर्थक देश के हर कोने में राजग से जुड़ रहे हैं। अभी-अभी तेलुगु देशम पार्टी के राजग में शामिल होने की खबर आ रही है। ये सभी आंकड़े आंध्र प्रदेश के इस गठबंधन से पहले के सर्वे के हैं, अब तो आंकड़ा काफी आगे जा चुका होगा।

एक तरह जहां हर दिन राजग अपनी जमीनी पकड़ और अधिक मजबूत कर रहा है, कांग्रेसनीत संप्रग ढलान पर तेज गति से लुढ़कता हुआ नीचे गिर रहा है। टाईम्स नाऊ-इंडिया टीवी-सी वोटर ने अपने जनवरी-फरवरी 2014 के सर्वे में संप्रग को 101 और कांग्रेस को 89 सीटें दी हैं। अपने फरवरी 2014 के सर्वे में एबीपी न्यूज- निलसन ने संप्रग के लिए 92 सीटों की भविष्यवाणी की है। एनडीटीवी-हंसा ने अपने मार्च 2014 के सर्वे में 123 सीटें जबकि सीएनएन-आईबीएन-लोकनीति-सीएसडीएस ने मार्च 2014 के अपने सर्वे में संप्रग के लिए 111-123 सीटों की भविष्यवाणी की है। किसी भी हाल में कांग्रेस सैंकड़े का आंकड़ा पार करने की स्थिति में नहीं है, यह पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है।

सभी सर्वे इस बात पर अब एकमत हैं कि राजग एक बड़ी जीत की ओर बढ़ चुकी है। ज्यों ही देश में चुनावों की घोषणा हुई और विभिन्न दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, पूरे देश में उत्साह एवं उमंग का वातावरण बन गया, क्योंकि लोगों के लिए वह समय आ गया जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूरा देश परिवर्तन की बाट जोह रहा था। यह पूरा वातावरण विभिन्न सर्वे में परिलक्षित हुआ, और हर सर्वे के साथ पहले से भी अधिक सीटों की भविष्यवाणियां होने लगी हैं। कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, नीतिगत पंगुता, कमजोर नेतृत्व, संकट के बाद संकट,

लूट पर लूट- यह बात लोगों के मन-मस्तिष्क में ताजा है। कांग्रेस जो इस बात में विश्वास करती है कि 'लोगों की स्मृति छोटी होती है', उसे अब अपने कुकर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है। लोग अब अटलजी के नेतृत्व वाली भाजपा नीत राजग सरकार को याद कर रहे हैं जब तीव्र विकास, राष्ट्र निर्माण की परियोजनाएं, महंगाई और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का बोलबाला था। अब लोगों को श्री नरेन्द्र मोदी से आशा है, उनका सुशासन का रिकार्ड, विकास के सपने, राजनैतिक इच्छाशक्ति, दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता एवं भारत को एक समृद्ध, शक्तिशाली एवं विकसित देश बनाने का जज्बा- इस सबसे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

अब जबकि सभी सर्वे अपने आंकड़ों को सुधार कर राजग को और अधिक से अधिक सीटें दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि 'मिशन 272' अब भाजपा के पहुंच में है। अब इसमें कोई शंका नहीं कि भाजपा नीत राजग 272 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। लोगों में व्याप्त उत्साह और उमंग जो एक दशक की निराशा और त्रासदी से बाहर निकलना चाहते हैं इस बात की ओर इंगित कर रही है कि श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को लोगों का अद्‌भुत समर्थन प्राप्त है। यह भारी जनसमर्थन एक लहर के रूप में दिखाई दे रहा है और इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि लोग जब तक अपना मतदान करेंगे यह 'सुनामी' में परिवर्तित हो चुका होगा। भारी जनसमर्थन जो जातीय, सांप्रदायिक, लैंगिक और क्षेत्रीय भेदभाव को तोड़कर राष्ट्रीय हित में एकजुट हो रहा है उन लोगों के लिए एक पाठ है जो इन आधारों पर राजनैतिक लाभ के लिए समाज को बांटते हैं। श्री नरेन्द्र मोदी को पूरे देश में मिलता भारी जनसमर्थन के संदर्भ में भाजपा के 'मिशन 272+' के लक्ष्य में सुधार की आवश्यकता है। अब लक्ष्य 300+ होना चाहिए। ■

भाजपा ने 'संप्रग के खिलाफ आरोप-पत्र' जारी किया

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को कम किया है और खुद मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम तरह के समझौते किये।

भाजपा ने 'कांग्रेस नीत की संप्रग सरकार के दस वर्षों का काला युग' नामक आरोप पत्र जारी करते हुए यह आरोप लगाया।

आरोपपत्र में कहा गया, ''प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को नष्ट करने में सोनिया और राहुल बराबर के भागीदार हैं। वे बिना किसी उत्तरदायित्व के सत्ता की असीमित शक्तियां अपने पास रखना चाहते थे। कई अवसरों पर घटित भारी गलतियां और अनियमितताएं इन दोनों की स्वीकृति और अनुमोदन से हुई हैं।''

राज्यसभा में भाजपा के उपनेता श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी इस आरोपपत्र में कहा गया कि डॉ. मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर प्रकार का समझौता किया। प्रधानमंत्री ने किसी भी अवसर पर लगातार हो रहे घोटालों और जनता के पैसे की लूट को रोकने में सक्रियता नहीं दिखायी। इन्हीं कारणों से इस सरकार को आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार कहा गया। इसमें आरोप लगाया गया, ''घोटालों के कई प्रकरणों में स्वयं प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका संदेह के गंभीर दायरे में है।''

प्रधानमंत्री पर भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले बोर्ड के 'सीईओ' के बतौर कार्य किया, जहां राहुल उनके 'डिप्टी' थे।

आरोपपत्र में कहा गया कि संप्रग के शासन में प्रधानमंत्री पद का अवमूल्यन हुआ, इसकी गरिमा के साथ समझौता किया गया एवं लचर शासन प्रणाली का खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ा और असुरक्षा की भावना से देश की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय छवि पर गहरा आघात लगा।

इसमें ये आरोप भी लगाया गया कि संप्रग के 10 साल के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाश कर दिया गया। इसमें कहा गया कि 2004 में जब संप्रग ने सत्ता संभाली थी, उस समय राजग से उसे विरासत में 8.5 प्रतिशत की विकास दर मिली थी, लेकिन आज 10 साल के बाद ये 4.5 प्रतिशत पर औंधे मुंह गिर गयी है। आरोपपत्र में कहा गया है कि सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रही और रुपए की कीमत में जितनी गिरावट संप्रग शासन काल में हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। आतंकवाद के संदर्भ में इसमें कहा गया कि वोट बैंक की राजनीति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है। इसके अनुसार सरकार के मंत्रियों द्वारा 'भगवा आतंक' जैसे शब्दों के प्रचलन के कारण उसे और बढ़ावा मिला। ■

भाजपा का घोषणा-पत्र जारी

सुशासन एवं विकास का संकल्प

भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में सुशासन और समेकित विकास का वादा करते हुए भारत का भाग्य बदलने के संकल्प को दोहराया। भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में समाज के सभी वर्गों के उत्थान की बात कही है। घोषणापत्र में वादा किया गया है कि

अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अलावा उद्योग के क्षेत्र में उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। भाजपा ने सत्ता में आने पर अपराधियों को राजनीति से बाहर करने, काले धन को वापस लाने का काम प्राथमिकता के आधार पर करने, खाद्य सुरक्षा का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने, कर प्रणाली को तार्किक और आसान बनाने, मल्टी ब्रांड खुदरा निवेश में एफडीआइ का समर्थन नहीं करने जैसे वादे भी किए हैं।

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं की ओर से 7 अप्रैल को नई दिल्ली में जारी किए गए 52 पन्नों के घोषणापत्र में कहा गया कि पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं को तलाशने के अपने रुख को दोहराती है।

समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर घोषणापत्र में कहा गया कि संविधान की धारा 44 में समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध है जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाएगा। पार्टी ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 का हटाने के अपने दृष्टिकोण पर पार्टी कायम है और रहेगी। इसमें कहा गया कि कश्मीरी पंडितों की अपने पूर्वजों की भूमि में ससम्मान, सुरक्षित और सुनिश्चित आजीविका के साथ वापसी सुनिश्चित करना भाजपा की प्राथमिकता होगी।

अल्पसंख्यकों से घोषणापत्र में वादा किया गया कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अलावा उद्योग के क्षेत्र में उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें कहा गया है- यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के इतने बरसों बाद भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा समूह, विशेषकर मुसलिम समुदाय गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है। आधुनिक भारत समान अवसर वाला होना चाहिए। भाजपा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत के विकास में सभी समुदायों की समान भागीदारी होनी चाहिए।

काले धन के बारे में घोषणापत्र में कहा गया कि भाजपा की सरकार आने पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश न्यूनतम करके ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी कि काला धन पैदा ही नहीं होने पाए। भाजपा ने विदेशी बैंकों और समुद्र पार के खातों में जमा काले धन का पता लगाने और उसे वापस लाने के कार्य को प्राथमिकता देने का वादा किया।

संघीय ढांचे के बाबत भाजपा ने केंद्र कहा कि और राज्यों को ऐसा कार्यतंत्र बनाना होगा जिससे आपसी रिश्ते सद्भावपूर्ण हों और हर राज्य की स्वाभाविक परेशानियां व्यापक रूप से निपटाई जा सकें। इसमें कहा गया है कि टीम इंडिया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में बैठी टीम ही नहीं होगी बल्कि मुख्यमंत्रियों और अन्य अधिकारियों को भी इसमें समान भागीदार बनाया जाएगा। ■

राजग का लगातार विस्तार हो रहा है : राजनाथ सिंह

भाजपा के चुनाव घोषणा-पत्र को जारी करने से पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसे जारी करना औपचारिकता भर नहीं है। यह केवल घोषणा पत्र नहीं बल्कि पार्टी का संकल्प पत्र है जिसमें किए हर वादे का पूरा किया जाएगा। भाजपा उस पार्टी (कांग्रेस) जैसी नहीं जिसने दशकों तक देश पर राज किया लेकिन जनता से किए वादों को नहीं निभाया। उनका मानना है कि यदि कांग्रेस ने रत्ती भर भी वादा पूरा किया होता तो भारत आज एक महाशक्ति बन चुका होता। कांग्रेस सरकार का पैदा किया विश्वास का संकट दूर करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता दूर करना मुख्य लक्ष्य। इसके बाद, पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का जिक्र करते राजनाथ सिंह ने कहा कि चारों दिशाओं से बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। उन्हें वह दिन याद है जब मोदी को पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। तब, राजनीतिक दलों ने इतना हो हल्ला मचाया मानो वह और भाजपा दोनों के लिए अछूत हों लेकिन आज 25 पार्टियां राजग से जुड़ चुकी हैं यानी माहौल बदल गया है। उनकी याद में आजादी के बाद शायद ही दूसरा ऐसा कोई नेता हो जिस पर मोदी से अधिक हमले किए गए होंगे किंतु, उन्होंने इनसे उबरकर यह बात साबित कर दी कि विधाता जिससे बड़ा काम लेना चाहता है उसकी कठोर परीक्षा भी लेता है। मोदी विधाता की परीक्षा में पूरी तरह पास हो गए हैं।

सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है : डॉ. जोशी

भाजपा घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और इसे व्यापक बातचीत के बाद तैयार किया गया है। डॉ. जोशी ने कहा कि घोषणापत्र तैयार करने के लिए हमने समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की। देश-विशेष के अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के सुझावों के आधार पर हमने यह घोषणापत्र तैयार किया है। घोषणापत्र के लिए हमें 1 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।

अच्छे दिन आने वाले हैं : सुषमा स्वराज

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने घोषणा पत्र को पार्टी की नीतियों का दस्तावेज बताते हुए कहा कि इसमें वर्तमान स्थिति से उबरने की राह दिख रही है। इस समय देश ठप पड़ा हुआ है। उद्योग बंद हैं और व्यापार मंद। फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, मंत्री निर्णय नहीं ले रहे, अफसर दस्तखत नहीं कर रहे। भाजपा ने देश को चलाने का संकल्प लिया है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने पर पार्टी देश को दौड़ा देगी और, इस सर्व समावेशी दौड़ में समाज का हर वर्ग शामिल होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि एक अंतर बिल्कुल स्पष्ट है और वो यह कि कांग्रेस ने विदेशी पूंजी की बैसाखी पर विकास का वादा किया है जबकि भाजपा ने भारत को

भारतीयों के आधार पर श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया है। व्याकुल निराश, नाउम्मीद देशवासी चिंता न करें क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं।

बदइरादे से कोई काम नहीं करूंगा : नरेन्द्र मोदी

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार, घोषणा पत्र चुनावी रस्म अदायगी भर नहीं बल्कि उनके लिए दिशा, लक्ष्य व प्रतिबद्धता है। दो शब्दों में कहा जाए तो भाजपा सुशासन व विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी का उद्देश्य भारत को सक्षम व सामर्थ्यवान बनाना है। दिल्ली में एक ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए जिसे दुनिया आंख न दिखाए बल्कि आंख मिलाने को आतुर हो। भारत भी किसी को आंख न दिखाए बल्कि उससे आंख मिलाकर तरक्की करता जाए। आने वाले समय में जब उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा तब वह लोगों की आशा-अपेक्षा को पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें भरोसा है कि वह इसी कार्य संस्कृति के बल पर अपना उद्देश्य हासिल करेंगे। उनका लक्ष्य होगा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और रास्ता होगा 'सबका साथ-सबका विकास।' पार्टी से उन्हें जो दायित्व मिला है, एक व्यक्ति की हैसियत से वह यह कहना चाहते हैं कि इसे निभाने में कभी कोई कमी नहीं रहने देंगे। अपने लिए कभी कुछ भी नहीं करेंगे। और बदइरादे के साथ कभी कोई काम नहीं करेंगे।

ऐसा आनंद कभी महसूस नहीं हुआ : लालकृष्ण आडवाणी

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष घोषणा पत्र की सराहना करते श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि इसमें एक भी दोष निकालना कठिन है। बीसवीं शताब्दी भले पश्चिमी देशों की शताब्दी रही हो लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने में भाजपा सफल होगा। उन्हें यह विश्वास है कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पांच सालों के दौरान पार्टी वह सब कर गुजरेगी जो बीसवीं सदी में देश करना चाहता था। श्री मोदी की प्रशंसा करते हुए आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम के ऐलान के बाद चुनाव नतीजों पर जैसा असर नजर आ रहा है वह अद्भुत है।

उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में न तो ऐसा देखा न ही सुना। उन्हें जितने आनंद का अनुभव सोलहवीं लोकसभा के चुनाव में हो रहा है उतना पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ।■

प्रमुख बिन्दु

- अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संविधान के दायरे के भीतर तमाम संभावनाएं तलाशेगी पार्टी।
- धारा 370 हटाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम।
- जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े उपाय करने और विशेष अदालतें स्थापित करना।
- मूल्य स्थिरता कोष का गठन।
- एकल राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना।
- युवाओं को स्व-रोजगार की ओर उन्मुख करना और रोजगार कार्यालयों को करिअर केंद्रों में बदलना।
- टीम इंडिया पहल की स्थापना, जिसमें प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री समान भागीदार के रूप में शामिल होंगे।
- राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता का प्रावधान और राज्यों की क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना।
- पूर्वोत्तर में बेहतर जुड़ाव व ढांचागत विकास पर जोर।
- बगावत से सख्ती से निपटना।
- लोगों की भागीदारी से नदियों की सफाई का व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
- आतंकवाद-निरोधी तंत्र को फिर से प्रभावी बनाने और आतंकवाद से जुड़े मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था।
- गुप्तचर एजेंसियों को राजनीतिक दखल से मुक्त करने का वादा।
- डीआरडीओ को मजबूत किया जाएगा और चुनिंदा रक्षा उद्योगों में एफडीआई सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा।
- गांव स्तर तक गैस ग्रिडों और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना।
- बहुत तेज गति की हीरक चतुर्भुज 'बुलेट' ट्रेन परियोजना।
- पर्यटन के विकास के लिए 50 नए पर्यटन सर्किट।
- माध्यमिक स्कूल शिक्षा और कौशल विकास का सार्वभौमिकरण व राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी की स्थापना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना। यूजीसी का पुनर्गठन कर इसे उच्च शिक्षा आयोग में बदलना।

कोडरमा (झारखंड)

भाजपा की सरकार आते ही होगा देश का विकास : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2014 को कोडरमा (झारखंड) में आयोजित एक जनसभा में दिए गए भाषण के मुख्यांश :

ते रह वर्ष पहले इस झारखंड राज्य के बनने के बावजूद अभी तक बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। मैं मानता हूं कि 10 वर्षों के अंदर किसी राज्य या देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है। मुझे जानकर आश्चर्य होता है कि झारखंड की आधी

से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर है। यहां बडी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं।

हमारी सरकार झारखंड में रही है, लेकिन थोड़े समय के लिए रही है। स्थायी सरकार चलाने का मौका कभी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में नहीं मिला है। जिस दिन पूर्ण बहुमत के साथ आप झारखंड विधानसभा में हमारी सरकार बना देंगे, हम इस राज्य का कायाकल्प कर दिखा देंगे। स्थायी सरकार बनाने का अवसर जिस भी राज्य में जनता ने हमें दिया है, वहां की सरकारों का कामकाज सराहनीय रहा है। आप नरेंद्र भाई के गुजरात को देखिए। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ को देखिए, जहां 24 घंटे की बिजली मुहैय्या कराई जा रही है।

झारखण्ड के साथ-साथ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, क्या इतना धन यहां मुहैय्या नहीं कराया जा सकता कि झारखंड का विकास हो सके। कांग्रेस ने 55 वर्षों तक देश में शासन किया है। मगर देश की किसी समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। क्या यह सच नहीं कि आजाद भारत में लगातार छह वर्षों तक महंगाई रोकने का काम किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार ने किया।

क्या कारण है कि जब-जब कांग्रेस की सरकार आती है, महंगाई बढ़ती चली जाती है। महंगाई बढ़ती है कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। साढ़े पांच लाख करोड़ का भ्रष्टाचार इस कांग्रेस की सरकार ने करवाया है। उसका थोड़ा भी अंश अगर इस झारखंड पर खर्च हो गया होता तो झारखंड की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता।

जिस दिन भाजपा की सरकार केंद्र में आएगी, हम छह महीने से एक साल के भीतर महंगाई पर काबू पा लेंगे। केन्द्र सरकार की एक एजेंसी है- नेशनल सैंपल सर्वे अश्वर्गेनाइजेशन। इसने अपने एक सर्वे में कहा है कि जब भाजपा की सरकार थी 1999 से 2004 तक, 6.7 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो 2004 से लेकर 2009 तक केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही केन्द्र में हमारी सरकार आती है, हम देश में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि पांच से लेकर सात वर्षों तक में हमारा नौजवान रोजगार को लेकर आश्वस्त हो जाएगा। हम हर नौजवान को सरकारी नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लए हर नवयुवक को छह-आठ महीने का प्रशिक्षण दिलवाएंगे। उसके बाद जो भी नौजवान अपना काम करना चाहता है, उसे भाजपा सरकार दो-तीन फीसदी ब्याज दर पर आसानी से बैंक ऋण मुहैय्या करवाएगी। हमारी जैसे ही सरकार आती है, यहां थर्मल पावर प्रोजेक्ट को शुरू करवाएंगे। मुझे भरोसा है कि जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार आती है, झारखंड में भी जल्द ही हमारी सरकार बहुमत के साथ बनेगी। पूरे हिन्दुस्तान में जितनी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, उसे बनवाने का काम किसी ने पहली बार शुरू किया, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया।

देश संकट के दौर से गुजर रहा है और इस दौर से कोई देश को निकाल सकता है तो देश की जनता ही निकाल सकती है। ■

नुआपदा, बालंगीर और राउरकेला, ओडिशा

देश को बर्बादी से बचाने के लिए बदलाव अति आवश्यक : नरेन्द्र मोदी

गत 4 अप्रैल को नुआपदा, बालंगीर और राउरकेला (ओडिशा) में विशाल रैलियों को सम्बोधित करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस की वंशवादी और विनाशकारी राजनीति की भर्त्सना की और लोगों से देश की सेवा करने के लिए एक सेवक को मौका देने की अपील की।

श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि 2014 चुनाव लोगों की आवाज हैं कि देश में परिवर्तन लाया जाए और उन लोगों को दण्डित किया जाए जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, अत: कांग्रेस और बीजेडी को समाप्त किया जाए और कहा कि नवीन बाबू 15 वर्षों से सत्ता में बैठे हुए हैं। इतने वर्षों में ओडिशा को क्या मिला? उनका कहना था कि नवीन बाबू, वंशवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है।

लोगों से कांग्रेस के झूठे वायदों पर भरोसा न करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कांग्रेस की काली करतूतों ने अनेकों उदाहरण पेश किए जिस कारण कि कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे अनेक गम्भीर मामलों का हल ही नहीं करना चाहती और यही कारण है कि राज्य को रोजगार ढूंढ़ने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। उन्होंने ओडिशा में विशाल विकास और दस्तकारी सम्बन्धी अनप्रयुक्त संभावनाओं पर बल देते हुए कहा कि राज्य और केन्द्रीय सरकारों को इस क्षेत्र की पर्यटन और विकास संभावनाओं की जरा भी चिंता नहीं है।

उनका यह भी कहना था कि आज देश में महिलाएं असुरक्षा में जीवन व्यतीत कर रही हैं और बतलाया कि केन्द्र द्वारा निर्भया निधि के अन्तर्गत बनाए गई निधि तक का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि फिर भी इस स्थिति में कांग्रेस का देशवासियों को मूर्ख बनाने का प्रयास रहता है। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए पूछा कि देश की सर्वोच्च 10 राज्यों में से 7 राज्यों में कांग्रेस-शासित राज्य हैं और हाल के राष्ट्रीय अपराध रिकार्डों को देखा जाए तो उनमें महिलाओं को अत्याचार भुगतना पड़ता है तो क्या यही केन्द्र की महिला सुरक्षा होती है?

पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री जुआल ओराम, वरिष्ठ नेता श्री दिलीप रे, श्री धीरेन्द्र सेनापति, श्री किशन साहू और श्री उपेन्द्र प्रधान रैली के दौरान उपस्थित थे। ■

की सत्ता के दिन गिने चुने दिन रह गए हैं। शाहजादे जी, मैडम सोनिया जी! हवा का रूख एकदम साफ है।

कांग्रेस की वंशवादी राजनीति पर हमला बोलते हुए और इससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए श्री नरेन्द्र मोदी का कहना था कि लोकसभा चुनाव 2014 एक तरफ दो प्रभावशाली राजनीतिक विरासत और एक चाय बेचने वाले के बेटे के बीच है जो देश की सेवा में जुटा है। श्री मोदी ने कहा कि आज लोकतंत्र की सत्ता है और

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

''कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब वोट बैंक राजनीति''

गत 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विशाल रैली के आयोजन में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस द्वारा चुनाव को साम्प्रदायिक बनाने की घोर निंदा की और कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में एक दम विफल रही है।

श्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा मुस्लिम नेताओं से अपने वोटों को न बंटने देने की अपील पर भी घोर आपत्ति की और कहा कि यह कांग्रेस का एक और प्रयास है जो चुनावों को जाहिर तौर पर साम्प्रदायिक बनाता है। श्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस हार चुकी है और इसीलिए अब वह सेक्युलरिज्म छोड़ कर खुलेआम साम्प्रदायिकता पर उतर आई है। जो कुछ भी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वह तो सीधा ही मजहब के आधार पर वोट मांगना है, जो इस देश के कानून के खिलाफ है। इस पर तो अपने आप ही संज्ञान लिया जाना चाहिए। आप बताइए कि क्या मजहबी आधार पर इस तरह की अपील की जानी चाहिए। खाली नारेबाजी मत कीजिए और फिर आप इस तरह भाईयों-भाईयों में बंटवारा कर देते हैं। दुख की बात है कि कांग्रेस की यही परम्परा रही है। सोनिया जी ने देश को गुमराह और विभाजित करने की कोशिश की है। लोग कभी भी इस प्रकार की राजनीति को माफ नहीं करेंगे।

श्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म का विचार मात्र एक चुनावी नारा है जिसका मतलब केवल 'बांटों और राज करो' है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म वोट बैंक की राजनीति है जब कि हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस 'बांटों और राज करो' पर चलती है तो हम पूरे देश को एकजुट, अखण्ड बना कर काम करते हैं। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है 'मजहब पहले', परन्तु हमारे लिए 'भारत प्रथम' है। यह हमारी निष्ठा की चीज है।

केन्द्र सरकार की कमजोरी और शक्तिहीनता को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि देश में मजबूत और स्थिर सरकार हो। श्री मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में दिल्ली में अगली सरकार बनाने में यूपी का गहरा अंशदान होता है, अत: भाजपा को वोट दें। हमें यूपी से अधिक से अधिक 'कमल' खिलाने की आवश्यकता है।

उन्होंने किसानों की आत्महत्या पर चिंता प्रगट करते हुए कहा कि इस कारण कांग्रेस की कृषि क्षेत्र के प्रति घोर लापरवाही प्रकट करती है। उन्होंने लोगों को बतलाया कि कांग्रेस 'मांस' का निर्यात कर 'पिंक रेवोल्यूशन' को प्रेरित करती है, परन्तु वह किसानों की दयनीय दशा को देख कर भी अनदेखी करती रहती है।

श्री मोदी ने कहा कि आज फील्ड मार्शल मानेक शॉ की 100वीं जयंती है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में ऐतिहासिक योगदान किया था। उन्होंने मार्शल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की और इस बात पर खुशी प्रगट की कि आज वह सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी श्री वी.के. सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं। ■

कुरूक्षेत्र और गुड़गांव (हरियाणा)

''हरियाणा सरकार की उपेक्षा से लोगों की समस्याएं बढ़ीं''

गत 3 अप्रैल को कुरूक्षेत्र और गुड़गांव की रैलियों में श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस 2014 का चुनाव हारने वाली पार्टी बन गई और इस बार का चुनाव एक तरह से अलग किस्म का चुनाव है जिसमें एक तरफ कड़ी मेहनत और लोगों का पसीना है तो दूसरी तरफ धनबल की शक्ति काम कर रही है।

श्री मोदी ने जनसभा में लोगों को विश्वास दिलाया कि वे हमारे सत्ता में आने पर हम जल्द से जल्द लोगों की समस्या का हल निकालेंगे, और उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल का स्मरण कराते हुए कहा कि उन्होंने देश की नदियों को जोड़ने का प्रयास किया था, परन्तु कांग्रेस के शासनकाल में इस दिशा में जरा भी प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार और केन्द्र सरकार की अदूरदर्शिता ने आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं होने दिया और इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि 'मैं हरियाणा को भलीभांति जानता हूं, उनके लोगों और किसानों की समस्याओं को समझता हूं।' श्री मोदी ने फिर कहा कि हरियाणा में जमीन का जबरदस्त घोटाला हुआ है, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पास एक पैसा न हो, वह रातोंरात 3 महीने में उसके बैंकों में (संभवत: इसका प्रसंग कांग्रेस के बहनोई राबर्ट वाड्रा से हो सकता है) करोड़ों की सम्पत्ति जमा हो जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने किसानों की जमीन बेच डाली और करोड़ों कमा लिए। आखिर उस व्यक्ति का उससे क्या सम्बन्ध रहा है। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी आचरण का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र ने कोयला घोटाला किया और पूरे देश को अंधकार में रखा।

श्री मोदी ने केन्द्र सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने लोगों की समस्याओं की अनदेखी की और कुरूक्षेत्र जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र के प्रति पर्यटन की संभावनाओं के बारे में विचार तक नहीं किया। इस संभावना की उपेक्षा के कारण अनेकों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुरूक्षेत्र और गुजरात में द्वारका का एक गहरा सह-सम्बन्ध है जिसमें भगवान कृष्ण का महत्व स्पष्ट है और उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा को इन दोनों क्षेत्रों में बहुत कुछ योगदान किया है।

रैली के दौरान श्री रामबिलास शर्मा, श्री मनोहर लाल, कैप्टन अभिमन्यु, श्री रतन लाल कटारिया, श्री राजकुमार सैनी और श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा के साथ भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। ■

नवादा एवं बक्सर (बिहार)

''कांग्रेस-मुक्त भारत बनाने की जरूरत''

गत 2 अप्रैल को श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के नवादा और बक्सर में बड़े पैमाने पर रैलियों में समर्थकों को संबोधित किया एवं 2014 के चुनाव में दिल्ली में एक मजबूत और स्थिर सरकार सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

बिहार के साथ अपने संबंध को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वह 'द्वारिका नगरी' से आए हैं जो यादव समुदाय से नजदीकी से जुड़ी हुई है। उन्होंने श्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में होने वाले दुष्कर्मों की निंदा करते हुए इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया कि बिहार के यादव समुदाय के नेता गोहत्या में लगे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। श्री मोदी ने कहा, "वही यदुवंश जो श्री कृष्ण और गाय की पूजा करते हैं, उन्हीं के नेता आज उन लोगों के साथ हैं जो जानवरों की हत्या को प्रोत्साहित करते हैं। मैं मुलायमजी और लालूजी से पूछना चाहता हूँ कि वे उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो गुलाबी क्रांति को प्रोत्साहित करते हैं।''

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार हरित क्रांति या श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के बजाय केवल गोहत्या के लिए सब्सिडी देकर 'गुलाबी क्रांति' में लगी हुई है। किसानों और उनकी कृषि उपज के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता, मटन निर्यात के लिए उनकी वरीयता के कारण ही देश का सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र को इस बात पर बहुत गर्व है कि वो मटन निर्यात में रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली में कृषि के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है लेकिन जानवरों की हत्या के लिए सब्सिडी का प्रावधान है।''

श्री मोदी ने हाल में गुजरात में हुए एक किसान सम्मान समारोह में बिहार से किसानों को भेजने से बिहार के मुख्यमंत्री के इंकार करने की आलोचना की और कहा, "हमने पूरे भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, लेकिन आपकी बिहार सरकार राजनीति की वजह से किसानों को आने की अनुमति नहीं दे रही है। राजनीति में हमारे विचारों और अवधारणाओं में अंतर हो सकता है लेकिन इस तरह की दुश्मनी नहीं हो सकती है। पर अहंकार आसमान से भी ऊँचा हो तो ऐसा हो सकता है।'' उन्होंने जल संसाधन और नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति की कमी के कारण किसानों की दयनीय हालत पर प्रकाश डाला और कहा कि कैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था पर कांग्रेस शासन के अधीन उस पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा के 2014 में सत्ता में आने के साथ ही इस मोर्चे पर भी तेजी आएगी।

मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, विदेश से काले धन की वापसी जैसी राष्ट्रीय चिंताओं के समाधान में उनकी अक्षमता के लिए कांग्रेस पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा पाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद विदेशी बैंकों में जमा अवैध धन की एक-एक कौड़ी वापस लाई जाएगी, और गरीबों की प्रगति के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कांग्रेस के 2009 में 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे को लोगों को याद दिलाते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये वादा आज की तारीख में भी अधूरा है और कांग्रेस के 2014 के घोषणा पत्र में फिर से इस वादे को दोहराया है। यह, और ऐसे कई अन्य अधूरे वादों को देखते हुए, उन्होंने कहा, यह समझ में आता है कि वो कांग्रेस घोषणा पत्र न होकर एक 'धोखा पत्र' था।

कांग्रेस के दुष्प्रचार का खण्डन करते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष से पूछा कि अगर देश के बुनियादी ढांचे के खाके के बनने में केंद्र सरकार ने 60 साल ले लिए हैं, तो

इसे पटरी में लाने में निश्चित रूप से कम से कम 600 साल लगेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष के 'राष्ट्र के लिए अधिक चौकीदारों की जरूरत' के बयान का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चौकीदारों की टीम श्री अशोक चव्हाण और श्री लालू प्रसाद यादव जैसे दागी मंत्रियों से मिलकर बनी है?

इस बात की पुष्टि करते हुए कि बिहार ही राष्ट्र के लिए परिवर्तन की अगुआई करेगा। श्री मोदी ने 2014 के चुनावों में भाजपा के लिए वोट करने और भारत को कांग्रेस-मुक्त बनाने के लिए लोगों से आग्रह किया। श्री मोदी ने लोगों से नवादा से भाजपा के उम्मीदवार श्री गिरिराज सिंह समर्थन देने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने ऐसे भारत बनाने की जरूरत पर बल दिया जहाँ हर व्यक्ति के लिए एक घर सुनिश्चित किया जा सके, सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त एक घर, और हर व्यक्ति की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने वर्ष 2022 तक इस तरह के भारत निर्माण का आश्वासन दिया, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहा होगा। श्री मोदी ने कहा कि यदि हमारे गांव मजबूत हैं तो हमारे शहर भी मजबूत होंगे। हमारा ध्यान गांवों को विकसित करने की तरफ है। एक शहर में उपलब्ध सुविधाओं को गांवों में उपलब्ध कराना चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम एक ऐसा भारत बना सकें जहाँ कोई भी बेघर न हो।

श्री मोदी ने गत अक्टूबर में बिहार में अपनी रैली के दौरान भारी भीड़ की उपस्थिति को याद करते हुए कहा कि बम विस्फोटों के बावजूद लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। श्री मोदी ने लोगों के साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर भारत में कहीं भी तेज लहर है तो यह बिहार में है। 27 अक्टूबर को मैंने बिहार का मिजाज देखा। मैं जहाँ भी गया मैंनें लोगों के संकल्प के बारे में बात की।

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता श्री नंद किशोर यादव, श्री गिरिराज सिंह, श्री अश्विनी चौबे और श्री आर.के. सिंह उपस्थित थे। ■

बरेली (उत्तर प्रदेश)

''कांग्रेस, सपा और बसपा जानते हैं कि वे नहीं जीतेंगे इसलिए वे अस्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं''

गत 1 अप्रैल को बरेली (उत्तर प्रदेश) में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के तहत एक स्थिर सरकार बनाने का आश्वासन दिया और 'सबका' (सपा, बसपा और कांग्रेस) के आसन्न विनाश की घोषणा की। कांग्रेस की झूठे वादे और विभाजनकारी रणनीति बनाकर हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाने की रणनीति की कड़ी आलोचना करते हुए श्री मोदी ने भारत के लोगों से भाजपा को वोट देने और देश की सेवा के लिए 'सेवक' को एक मौका देने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने 2004 के बाद से कांग्रेस के शासन के अधीन कुशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अब केवल कागजी कार्रवाई करने के बजाय सही में कार्य करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि 'सबका' (सपा, बसपा और कांग्रेस) के शासन के खत्म होते ही इस कुशासन का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर वे राष्ट्र को चलाने के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सबकुछ वैसे ही चलता है। सरकारों को आम लोगों को सुनने की जरूरत है।

कांग्रेस के लगातार झूठ को माफ न करते हुए श्री मोदी ने उनके घोषणा-पत्र को 'धोखा पत्र' बताया, जिसमें पिछले

एक दशक में उनके द्वारा किए गए कई अधूरे वादों को दोहराया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से भाजपा को वोट देने

और देश की सेवा करने के लिए एक ' सेवक' को मौका देने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि 60 साल तक आपने शासकों को चुना है। आपने देखा कि उन्होंने क्या किया। अब आपको तय करना है। अब लोगों को शासक की नहीं एक सेवक की जरूरत है। जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तब कांग्रेस उत्सव मना रही थी। हम उसे कुचल देंगे। लेकिन क्या हुआ है। विरोधियों ने कहा कि भाजपा को सहयोगी नहीं मिलेंगे, कई लोग साथ छोड़ देंगे लेकिन देश भर में नए दोस्त हमसे जुड़े हैं।

बरेली में श्री संतोष गंगवार जी के शासन के तहत हुए विकास की तुलना करते हुए श्री मोदी ने कहा आज यह क्षेत्र विकास के मोर्चे पर रायबरेली से ज्यादा बेहतर है, जो उनके सांसदों के मजबूत नेतृत्व का दावा करते हैं। श्री मोदी गुजरात में फैले हुए पतंग उद्योग में बरेली के योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि बरेली के मांझा के बिना गुजरात की पतंग उड़ नहीं सकती है। हमारा संबंध इस तरह का है। हमारी पतंग उद्योग ने गरीब से गरीब लोगों की एकीकृत किया गया है। उद्योग में शामिल लोगों में से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के हैं। हमने गुजरात के पतंग उद्योग 500 करोड़ तक ले कर गए हैं और इस प्रकार से गरीबों की मदद की है।'' इस प्रकार उन्होंने गुजरात में भाजपा के तहत फैले पतंग उद्योग और उत्तर प्रदेश में सपा और केन्द्रीय सरकार के अधीन आई मांझा उद्योग में गिरावट पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने लगातार हो रही किसानों की आत्महत्याओं और आतंकवादियों द्वारा सैनिकों की हत्याओं के प्रति कांग्रेस की उदासीनता पर दुख व्यक्त किया। कांग्रेस के इस असहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण ने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के 'जय जवान, जय किसान' के नारे को उलटते हुए 'मर जवान, मर किसान' का नया नारा गढ़ा है। उन्होंने कहा कि कैसे गरीब कांग्रेस के लिए वोटबैंक के रूप में ही सामने आता है, और केवल चुनाव के दौरान ही उसको संबोधित किया जाता है। केंद्र सरकार के इस असंवेदनशील दृष्टिकोण का विरोध करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गरीबों और उनकी गरीबी को वही समझ सकता है जिसने गरीबी का जीवन जिया हो, लेकिन कांग्रेस इससे मीलों दूर है। कांग्रेस के लिए सभी 365 दिन अप्रैल मूर्ख दिवस हैं। वे चुनाव से पहले गरीबों की बात करते हैं और उनके नेता गरीबी को मन की एक अवस्था बताते हैं।

श्री मोदी ने लंबे समय से इंतजार कर रही भीड़ के साथ सहानुभूति जताते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी दृढ़ता व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह देश में आशा की एक नई लहर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और आश्वासन दिया वह भाजपा के तहत राष्ट्र के पास एक स्थिर सरकार होगी। श्री मोदी ने चेती चाँद के अवसर पर शुभकामनाएँ भी दी।

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी, श्री राजेश अग्रवाल और श्री धर्मपाल इस अवसर पर उपस्थित थे।■

कोडरमा (झारखंड)

''समाज के सभी तबकों के विकास पर है भाजपा का ध्यान''

गत 2 अप्रैल की सुबह श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के कोडरमा में एक विशाल रैली को संबोधित किया। राष्ट्र के विकास में 'जन भागीदारी' की अवधारणा पर बल देते हुए श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि भाजपा का ध्यान समाज के सभी तबके, विशेष रूप से गरीबों के विकास पर है। श्री मोदी ने लोगों का आह्वान करते हुए हुए कहा कि उन्हें अब यह निर्णय लेना है कि क्या दागी मंत्रियों वाली कांग्रेस सरकार देश को बचा सकती है?

कांग्रेस उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी कि देश को कई 'चौकीदारों' की आवश्यकता होगी, का विरोध करते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के भीतर दागी मंत्रियों की उपस्थिति के बारे में पूछताछ करते हुए कहा कि क्या उनकी टीम राष्ट्र की रक्षा करने में पर्याप्त सक्षम है। कांग्रेस के उन मंत्रियों पर हमला करते हुए जो घोटाले करने में तल्लीन थे, श्री मोदी ने कहा कि क्या कांग्रेस को नहीं बताना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों के साथ गठजोड़ किया? क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? कुछ लोग जेल से आए हैं। आपके चौकीदार अशोक चव्हाण, लालू जी हो सकते है? क्या ये हैं आपके चौकीदार? क्या राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। कांग्रेस की भ्रष्ट प्रणाली पर आगे बोलते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को याद दिलाया कि उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस बात पर टिप्पणी की थी कि कैसे कांग्रेस शासन के तहत दिल्ली सरकार द्वारा मंजूर किया

गया वास्तविक धन लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाता था। श्री मोदी ने पूछा कि क्या कांग्रेस का हाथ इसके लिए जिम्मेदार था?

कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए कृषक समुदाय को सशक्त बनाने में कांग्रेस की अज्ञानता और लापरवाही को स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के अथक प्रयासों से बढ़ा हुआ उत्पादन केंद्र की उचित भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने की पहल की कमी के कारण सड़ रहा है। लापरवाह कांग्रेस ने अपनी करतूतों को शराब निर्माताओं को शराब बनाने के लिए सस्ते दाम पर अनाज देकर और भी खराब कर दिया, जबकि लाखों गरीबों को भूखे छोड़ दिया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के 'जय जवान जय किसान' के आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लापरवाही के कारण इस मंत्र का अर्थ बिगड़ गया है क्योंकि कांग्रेस किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने के बजाय केवल बेकार की कागजी कार्रवाई में लिप्त है। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी सरकारी कार्यालयों में नहीं होती है। हमें अपने किसानों के हाथ मजबूत करने हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए चिंतित नहीं है। कितने किसानों को पता है कि हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय हैं.. समन्वय बहुत ही खराब है।

यह बताते हुए कि कैसे कांग्रेस तकनीकी प्रगति और गुणवत्ता बढ़ाकर झारखंड में कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में विफल रही है, विशेष रूप से अभ्रक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में, श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। और लोग इसकी वजह से पीड़ित हैं। जब भारत की विकास यात्रा वातानुकूलित कमरों में बैठकर तय की जाती है तो फिर यह देश के गरीबों के साथ जुड़ नहीं पाती है। उन्होंने कहा कि कैसे केन्द्र सरकार की अनुचित और हानिकारक नीतियों के कारण कृषि उपज की चमक खत्म हो रही है। और कहा कि "किसानों के कल्याण के बारे में हम और आप जो समझते हैं वो दिल्ली को समझ में नहीं आता है। मैं यही बात रखना चाहता हूँ कि वे इन मूल बातें को समझ नहीं पाते हैं।

श्री मोदी ने कृषि उत्पादन में नई रणनीति की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि गुजरात ने अपने किसानों के लिए यह सुनिश्चित करने की दिशा में उत्साह के साथ काम किया था और यहां तक कि देश भर के प्रगतिशील किसानों, जिनमें से 12 झारखंड के थे,की सराहना की थी। उन्होंने दिल्ली को भी प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करना चाहिए था लेकिन वे इस बारे में नहीं सोचते हैं। हमें यहां के किसानों को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला।

राष्ट्र में जरूरी बदलाव लाने की आवश्यकता का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि एक 'सेवक' के रूप में काम करके केवल 60 महीने की अवधि में वह पिछले 60 साल के दुष्कर्मों को खत्म कर देंगे और देश की प्रगति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने 2014 के चुनाव में लोगों से वोट करने और मजबूत और स्थिर सरकार सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में 300 कमलों को भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव सत्ता पर कब्जा करने पर केंद्रित हो गया है। यह लोकतंत्र का एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। इसके बजाय चुनाव द्वारा लोगों को विकास यात्रा का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तब भारत आगे बढ़ेगा। यदि भारत को कांग्रेस शासन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करनी है, तो भाजपा को आप सभी से 300 कमल की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कोडरमा का झुमरी तलैया शहर कला और संस्कृति में अपनी विशेषता के लिए देश भर में लोकप्रिय है।

इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने श्री मोदी को भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित करते हुए बताया कि कैसे पूरे राष्ट्र में इस तरह की लहर है- लहर है श्री मोदी के लिए वोट करने की और 'भारत विजय' सुनिश्चित करने की।

प्रदेश अध्यक्ष श्री रवीन्द्र राय और श्री सरजू राय भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ■

गुमला और चतरा (झारखंड)

''कांग्रेस ने आदिवासियों के कल्याण की चिंता कभी नहीं की''

2014 के चुनाव में भाजपा को वोट देकर भारत के विकास के नये युग के लिए समर्थन देने की अपील जनता से करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 मार्च को गुमला और चतरा में भारत विजय रैलियां संबोधित करते हुए कहा कि 16वीं लोक सभा का यह चुनाव वर्ष 2014 में है और झारखंड की 14 सीटों के लिए है। यहां सभी 14 सीटों पर कमल का फूल खिलना चाहिए।

माओवादियों से हथियार डालने और आतंक छोड़ने की अपील करते हुए श्री मोदी ने उन्हें हल और कलम उठाने और विकास लाने को कार्य करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश को याद करते हुए युवाओं को हत्या और आतंक का माओवादी रास्ता छोड़कर शांति और तरक्की का मार्ग अपनाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का संदेश दिया। लेकिन माओवाद से प्रभावित युवकों ने हथियार उठा लिये हैं और सड़कों पर खून बहा रहे हैं। हमारी धरती को खून के रंग की नहीं बल्कि तरक्की के रंग की जरुरत है। आइये, किसानों की मेहनत से इस धरती को हराभरा बनायें। माओवादियों के हाथ में बंदूक नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह उनके हाथ में कृषि के औजार और कलम होने चाहिए ताकि वे दूसरों की सेवा कर सकें। रास्ता और कलम, हल और पसीने का है, खून का नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि लोकतंत्र की ताकत हमेशा आतंक और बंदूक की ताकत से अधिक है।

श्री मोदी ने झारखंड राज्य के गठन के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अथक प्रयासों को याद किया और बताया कि किस तरह यह भाजपा के शासन में संभव हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस लगातार सत्ता में रहती तो झारखंड का गठन कभी नहीं हो पाता। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कई सरकारें आयीं लेकिन उन्होंने झारखंड की कभी चिंता नहीं की। अब जबकि इसका गठन हो गया है, देखिये, वे इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मत भूलिये कि पंडित नेहरु ने झारखंड बनाने के विचार का मजाक उड़ाया था। यह अटलजी थे जिन्होंने हमको झारखंड दिया। श्री मोदी ने बिहार के उन नेताओं से भी सवाल किया जिन्होंने राज्य के गठन का विरोध किया था। उन्होंने पूछा कि ऐसे नेता अब कहां गायब हो गये हैं।

आदिवासियों के लिए चिंता के अभाव के लिए कांग्रेस पर हमला करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ

समय पहले तक आदिवासियों के अस्तित्व से भी वाकिफ नहीं थी। हालांकि उन्होंने कई वर्ष तक शासन किया लेकिन आदिवासियों के कल्याण की चिंता कभी नहीं की। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी समुदायों की चिंता नहीं करती। वर्ष 2004 तक आदिवासी समुदायों के विकास के लिए कोई नया मंत्रालय नहीं था। अगर कोई दल जो आदिवासियों की सेवा कर सकता है तो वह भाजपा है। हमने उनके विकास के लिए योजनाएं बनायी हैं। श्री मोदी ने बताया कि श्री वाजपेयीजी ने अलग मंत्रालय का गठन सुनिश्चित किया और आदिवासियों के विकास के लिए बजट आवंटित किया।

श्री मोदी ने झारखंड में व्याप्त अपार संभावनाओं का जिक्र किया जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। उन्होंने कहा कि कोयला और लौह अयस्कर के भंडारों से भरपूर होने के बावजूद झारखंड के युवाओं को रोजगार की तलाश में राज्यों में जाना पड़ता है और यह सब केंद्र और राज्य सरकार की नीति और नीयत के अभाव के चलते हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि सत्ताधारी सरकार का जोर अपने नागरिकों के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बजाय कोयला घोटाले के जरिये खुद को लाभ पहुंचाने पर है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं और पार्टियों को लगता है कि प्राकृतिक संसाधन भ्रष्टाचार के लिए बड़ा अवसर हैं। उन्होंने कोयला तक को भी नहीं छोड़ा।

गुजरात में खनन के क्षेत्र में किये गये क्रांतिकारी सुधार जैसे- अलग खनन नीति, खनन में कार्य के उपग्रह मानचित्र, कम्प्यूटरीकरण, वाहनों की निगरानी के लिए जीपीएस के इस्तेमाल आदि का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से राजसेवक में कई गुना वृद्धि हुई है। इस पहल को मैजिक (MAGIC - खनन प्रशासन और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सुशासन) नाम दिया गया।

इस पहल को भ्रष्टाचार को कम करने तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। श्री मोदी ने यह भी बताया कि किसानों को पर्याप्त पानी मुहैया कराने की मूलभूत पहल किस कदर कृषक समुदाय की बेहतरी के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। ड्रिप सिंचाई और अन्य सुधारों के इस्तेमाल से किसानों को पर्याप्त पानी मुहैया कराने की गुजरात की कृषि की सफल कहानी का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह तरीका झारखंड के लिए भी आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आयेगा।

केंद्र सरकार में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार, जिसके चलते अनगिनत भ्रष्टाचार हुए हैं, उसके लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमने सभी तरह के टैक्स के बारे में सुना है लेकिन दिल्ली में एक टैक्स था जिसका नाम है- जयंती टैक्स। यह टैक्स पर्यावरण मंजूरी के लिए था। मैं अनुभव से कह सकता हूं कि हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा...इरादे नेक होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसी भी पार्टी का घोषणापत्र पवित्र होना चाहिए लेकिन कांग्रेस ने इसकी पवित्रता खो दी है। उन्होंने 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में किये गये वादों को बार-बार दोहराने के लिए कांग्रेस हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई घटाने की बात हो या बेरोजगारी कम करने की सभी वादे पुराने ही हैं।

उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि जिस तरह एक उम्मीदवार को लिखित में हलफनामा देना होता है, वैसे ही प्रत्येक सत्तारुढ़ दल से उसके घोषणापत्र को पूरा करने की लिखित प्रतिबद्धता लेनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं- आप उम्मीदवारों से हलफनामा लेते हैं। नियम बनाइये- सरकार अपने घोषणापत्र के कितने वादों को पूरा करती है।

गुमला को वीरों की, बलिदानियों की और समाजसेविकों की भूमि करार देते हुए श्री मोदी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और भारत-पाकिस्तान युद्ध में यहां के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि यह भूमि बहादुरों की है। यह भूमि उन लोगों की है जिन्होंने दूसरों के लिए खुद का बलिदान दे दिया भले ही यह 1857 में हो या किसी अन्य युग में। उन्होंने प्रेरणादायी बाबा तिलका, विश्वनाथ सहदेव, नीलंबर और पीतांबर और परमवीर एलबर्ट एक्का की कहानी का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा को उनके अमूल्य योगदान के लिए सदैव याद किया जायेगा।

इस मौके पर रैली को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने श्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें भारत का भावी प्रधानमंत्री करार दिया। उन्होंने झारखंड की सत्ताधारी सरकार में व्याप्त कुशासन की चर्चा करते हुए कहा कि यह सरकार झारखंड की जनता के लिए नहीं बल्कि राज्य के लोगों को लूटने के लिए है।

इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अर्जुन मुंडा, श्री रघुवरदास, श्री सुमित सुदर्शन भगत, श्री कमलेश राव, श्री विजय मिश्र और श्रीमती विमला प्रधान भी मौजूद थे। ■

दिल्ली

''जनता को अपने ताजा अनुभव के आधार पर विकल्प चुनना चाहिए''

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली की जनता से सभी सात सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को चुनने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की असलियत उजागर करते हुए आप को कांग्रेस की बी टीम करार दिया। श्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को, उसके घोषणापत्र के लिए आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रत्येक दल के लिए घोषणापत्र पवित्र विषय माने जाते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे एक मजाक बनाकर रखा दिया है और इसमें वही सब वादे दोहराये हैं जिन्हें वह 2004 के घोषणापत्र से अब तक पूरा नहीं कर सकी है।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संस्थाओं की पवित्रता में भरोसा नहीं रखती। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि शहजादे ने प्राइमरी की नई प्रणाली शुरु की। उसने कहा कि यह राजनीति बदल देगी। 15 सीटें ढूंढ़ी गयीं जहां से उम्मीदवारों को टिकिट दिया जाना था। इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया, लेकिन अंत में इसका क्या हश्र हुआ? यह प्रणाली पनपने से पहले ही खत्म हो गयी। इस प्रणाली के तहत ही वड़ोदरा में एक उम्मीदवार तय हुआ था। लेकिन रातों रात उसका नाम काट दिया। वह अपनी खुद की क्षमता के आधार पर उम्मीदवार चुना गया था लेकिन रातों रात उसका नाम सूची से काट दिया। उसका एक ही अपराध है- वह दलित है। उस पर उम्मीदवारी छोड़ने को दबाव डाला गया। क्या दलित होना अपराध है? क्या एक दलित को अवसर नहीं मिलना चाहिए?

आम आदमी पार्टी की अवसरवादिता और अपरिपक्वता के लिए उस पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि पार्टी ने अभी परिपक्वता हासिल नहीं की है जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने आप को कांग्रेस की बी टीम करार दिया। उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में किस प्रकार का अनुभव हुआ? आपने कांग्रेस ए और कांग्रेस बी देखी। क्या गठबंधन है! पहले कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाओ, उसके बाद इस्तीफा देकर कांग्रेस की मदद के लिए पूरे देश का दौरा करो और पिछले दरवाजे से दिल्ली का प्रशासन कांग्रेस को सौंप दो। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव हारने के बावजूद दिल्ली का प्रशासन कांग्रेस के पास क्यों है? श्री मोदी ने कहा कि उन्हें भारत की चिंता नहीं थी। वे सिर्फ कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं

श्री मोदी ने याद किया कि भाजपा और जनसंघ कई वर्षों तक विपक्ष में रहे। उस समय भी जबकि उनकी टिकिट पर जीतने वाले पार्षदों की संख्या भी कम थी। फिर भी पार्टी ने अथक परिश्रम किया और सरकार को कठघरे में रखकर खुद जनता के निकट रहकर काम किया। उन्होंने उन लोगों से सवाल किया जो कैमरों के साथ दिल्ली के रैन बसेरों में गये थे। मोदी ने कहा कि उन लोगों ने अब दिल्ली को क्यों भुला दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो अनुभव चाहिए उसका स्पष्ट अभाव था। लोग गलतियों को माफ कर सकते

हैं लेकिन धोखे को नहीं। दिल्ली की जनता को अपने अनुभव के आधार पर निर्णय करना चाहिए।

यूपीए सरकार के शिथिल प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी दशक में किसी भी सरकार का प्रदर्शन इतना बेकार नहीं था जितना यूपीए सरकार का पिछले दशक में रहा है।

उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के प्रति कांग्रेस की गंभीरता का जिक्र भी किया। उन्होंने महिला सुरक्षा के प्रति भी यूपीए सरकार की उदासीनता को उजागर करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार निर्भय फंड से धनराशि खर्च करने में नाकाम रही है, इससे यह जाहिर होता है।

दिल्ली की 7 लोक सभा सीट से भाजपा के उम्मीरदवार- (डॉक्टर) हर्षवर्धन (चांदनी चौक), श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली), श्री महेश गिरि (पूर्वी दिल्ली), श्री प्रवेश वर्मा (पश्चिम दिल्ली) श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली), श्री मनोज तिवारी (पूर्वोत्तर दिल्ली) रैली में उपस्थित थे। श्री विजय कुमार मल्होत्रा और श्री विजय गोयल भी इस मौके पर मौजूद रहे।■

नांदेड़, अकोला (महाराष्ट्र)

''आइये, बाला साहेब ठाकरे के कांग्रेस-एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र और भारत के सपने को पूरा करें''

एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला और नांदेड में विशाल जनसभाएं संबोधित की। श्री मोदी ने लोगों से भाजपा-शिवसेना-आरपीआई और शेतकारी महायुती को समर्थन देने और पूज्य बाला साहेब ठाकरे के कांग्रेस और एनसीपीमुक्त महाराष्ट्र और भारत के सपने को हकीकत में बदलने की

अपील की। उन्होंने कहा कि आदरणीय बालासाहेब ठाकरे हमारे बीच यहां नहीं हैं लेकिन वह हमारे दिलों में जिन्दा हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम महाराष्ट्र और देश को कांग्रेस तथा एनसीपी से मुक्त करने के उनके सपने को पूरा करें। श्री मोदी ने कहा कि 2014 का लोक सभा चुनाव एनडीए के सुशासन का एजेंडा और यूपीए के कुशासन तथा भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई है।

नांदेड में ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने नांदेड के लोगों से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण को हराने का आह्वान किया। उन्होंने आदर्श घोटाले पर कांग्रेस नेतृत्व और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार से लड़ने की कांग्रेस उपाध्यक्ष की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष को श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ जांच के बारे में हाल की उनकी टिप्पणी याद दिलायी और पूछा कि क्या उन्हें टिकिट देकर पुरस्कृत करना ही कांग्रेस की जांच की परिभाषा है। उन्होंने टिकिट देने को शर्मनाक करार दिया और कांग्रेस में मौजूद बहुत 'आदर्श' श्रेणी के नेताओं पर टिप्पणी की।

उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए आदर्श सिर्फ भ्रष्टाचार या किसी के रिश्तेदारों को फ्लैट देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह सशस्त्र बलों के प्रति कांग्रेस के असम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की पवित्र भूमि पर मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम उन लोगों को नहीं बख्शेंगे जिन्होंने करगिल के हीरो को लूटा। हम स्वच्छ राजनीति के हिमायती हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं

कि हम ऐसा तंत्र बनायेंगे जहां भ्रष्ट भले ही किसी भी पार्टी का हो लेकिन उसके मामले का निपटारा सालभर के भीतर हो जायेगा। दोषी को सजा दी जायेगी और जिन लोगों को गलत ढंग से फंसाया गया है उन्हें रिहा किया जायेगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नेता किस पार्टी का है।

श्री अशोक चव्हाण द्वारा नांदेड से मौजूदा सांसद और उनके जीजा से टिकिट छीनने की घटना पर कड़ी टिप्पणी करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमें अपनी बहनों को अधिकाधिक देने की बात सिखायी जाती है लेकिन यहां एक व्यक्ति है जिसने अपनी बहन से उल्टा लिया है।

श्री मोदी ने यूपीए के कुशासन और पीड़ित किसानों के प्रति लगाव के अभाव की भी जमकर आलोचना की। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वह विदर्भ आये लेकिन उन्होंने यहां सब कुछ गुजरात के बारे में ही बोला। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष को याद दिलाया कि ये गुजरात के चुनाव नहीं हैं और उनको तथा उनकी पार्टी को जनता को बताना चाहिए कि पिछले दशक में उन्होंने जनता के लिए क्यों किया है। गुजरात के विकास का गुब्बारा फंटने संबंधी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वह 2007 और 2012 में गुजरात आये लेकिन गुजरात की जनता ने सच का साथ दिया। श्री मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को याद दिलाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन के उनके परिवार से नजदीकी संबंध हैं और इस फाउंडेशन ने गुजरात के विकास की सराहना की है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के चिंता के अभाव की आलोचना करते हुए एनडीए के पीएम उम्मीदवार ने कहा कि भारत के कृषि मंत्री महाराष्ट्र से हैं लेकिन वह किसानों को बचाने में अक्षम हैं। उनके पास क्रिकेट पर चर्चा करने का वक्त है लेकिन किसानों की पीड़ा के बारे में बात करने के लिए नहीं। अकोला में उन्होंने कपास किसानों की समस्याओं को उठाया और जिस ढंग से कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है उसके लिए कृषि मंत्री से सवाल किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है जबकि मांस के निर्यात को प्रोत्साहित करती है।

श्री मोदी ने कांग्रेस-एनसीपी नेताओं के राज्य और केंद्र में कुशासन और व्यापक भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वही भूमि है जिसने हमें शिवाजी महाराज दिये जो सुशासन के अग्रदूत थे लेकिन आज राज्य के नेता आदर्श और सीडब्ल्यू जी घोटालों में लिप्त हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये एलबीटी के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि एलबीटी कुछ नहीं सिर्फ लूटो-बांटो टैक्स है। यह टैक्स महाराष्ट्र के कारोबारियों को बरबाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को नहीं मालूम कि गरीबी क्या है और इससे पता चलता है कि गरीबों के प्रति उनकी सोच कैसी है।

श्री मोदी ने कालेधन का अहम मुद्दा भी उठाया और लोगों से पूछा कि कालाधन वापस आना चाहिए या नहीं, इसका जवाब लोगों ने हां में दिया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि एनडीए सरकार कालेधन की पाई-पाई वापस लायेगी और उस धन का इस्तेमाल गरीबों के विकास के लिए करेगी। कालेधन को वापस लाने के लिए कांग्रेस में प्रतिबद्धता के अभाव पर टिप्पणी करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे कालेधन को वापस नहीं लाना चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह धन किसका है। श्री मोदी ने निर्भय फंड की धनराशि इस्तेमाल नहीं होने पर वित्त मंत्री से भी सवाल किया और कहा कि इस तरह का अपमान महिलाओं के प्रति कांग्रेस में सम्मान के अभाव को दर्शाता है।

कांग्रेस और उसके सहयोगियों की असलियत उजागर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आम तौर पर निवर्तमान सरकार को हराने के लिए गठबंधन बनाये जाते हैं लेकिन इस उन्हें चनुाव जीतने से रोकने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वजह स्पष्ट है। जिन लोगों ने देश को लूटा है उन्हें मालूम है कि 16 मई के बाद उनका स्थान कहां है। श्री मोदी के इस बयान पर उपस्थित लोगों ने ताली बजाकर हर्ष प्रकट किया।

महाराष्ट्र के लोगों को गुडी पडवा की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लोगों से कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन को हराने की शपथ लेने और सुशासन के एक नये युग में प्रवेश करने का आग्रह किया। इस मौके पर अमरावती से सांसद और शिवसेना नेता आनन्दराव अदसुल, शिवसेना के वरिष्ठ नेता और विधायक सुभाष देसाई, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष देवेंद्र फडनवीस और महायुति के अन्य नेता मौजूद थे। नान्देड में श्री गोपीनाथ मुंडे ने भरोसा जताया कि महायुति महाराष्ट्र में सभी सीटें जीतेगा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की हार होगी। उन्होंने टोल-मुक्त महाराष्ट्र और किसानों के हितों की रक्षा करने वाला राज्य सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। ■

मुद्दा : कांग्रेस का घोषणा-पत्र

विफल आश्वासनों का स्तुतिगान

✍ एम. वेंकैया नायडू

कांग्रेस का घोषणापत्र धोखे का दस्तावेज है। यह देश की जनता से किया जाने वाला एक और धोखा है जिसके कारण उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसका उद्देश्य झूठे वादों और धोखाधड़ी के तरीकों से जनता को मूर्ख बनाना है, पर लोग काफी बुद्धिमान हैं। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस थक गयी है और सरकार में दो कार्यकाल के बाद उसके पास नये विचार नहीं हैं। 2014 का घोषणापत्र इसकी अभिव्यक्ति करता है। यह केवल पुराने और विफल विचारों की पुन: पैकेजिंग है। 2014 में किये गये अनेक वादे 2009 में विफल हो चुके हैं। घोषणापत्र अनेक ऐसे दावों से भरा है जिनको प्राप्त करना असंभव है जैसे वर्तमान चार प्रतिशत वृद्धि दर को बढ़ा कर आठ प्रतिशत पर पहुंचाना। इसके उलट कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पिछले 10 वर्षों में वृद्धि दर घटा कर 85 प्रतिशत से 46 प्रतिशत पर ला चुकी है।

कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि 2009 में किये वादों में से 90 प्रतिशत पहले ही लागू किये जा चुके हैं। यदि वास्तव में ऐसा ही मामला होता तो आज कांग्रेस वहां नहीं होती जहां वह है। 90 प्रतिशत की बात तो भूल ही जायें, वादों का 10 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है। इस दावे से बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? यह किये गये वादों के साथ पूरी तरह धोखा है। क्या कांग्रेसियों को याद है कि 2009 में तथा 2004 में क्या वादे किये गये थे?

- वादा था कि अनेक आयोग गठित किये जायेंगे जिनमें प्रशासनिक सुधार आयोग, असंगठित क्षेत्र उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एवं राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता परिषद् शामिल थे। उनका क्या हुआ?
- नीतिगत सुधारों की प्रक्रिया तेज की जायेगी। उसका क्या हुआ?
- केन्द्र सरकार की सहायता से सभी शहरों में बेघर लोगों तथा आप्रवासियों के लिए सस्ते सामुदायिक किचन स्थापित किये जायेंगे। ये किचन कहां हैं?
- सुनिश्चित किया जायेगा कि खास जोखिम वाले सभी लोगों के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो। इनमें अकेली महिला प्रमुख वाले परिवार, विकलांग एवं वृद्ध, शहरी बेघरबार, मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर, आदिम आदिवासी समूहों के सदस्य तथा 'अति पिछड़े' घोषित दलित समुदायों के लोग होंगे। ये सामाजिक सुरक्षायें कहां हैं?
- देश के प्रत्येक ब्लाक में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जायेगा। अगले पांच वर्षों तक हम प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल जोड़ेंगे। ये स्कूल कहां हैं?
- न्यूनतम समर्थन मूल्यों के साथ किसानों के दरवाजों पर खरीद सुनिश्चित की जायेगी। स्वामीनाथन समिति सिफारिशों का क्या हुआ? आठ साल बीत गये और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
- खेती के उत्पादों के मुक्त आवागमन तथा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर लगे नियंत्रण तथा ऐसे सारे नियमन हटाये जायेंगे जिनसे किसानों की आमदनी बाधित होती है। कोई कार्रवाई नहीं हुई।
- कानून द्वारा समान अवसर आयोग स्थापित करेंगे। क्या हुआ? सच्चर समिति समीक्षा समिति के अनुसार, 'अल्पसंख्यक जिलों के सरोकारों को संबोधित करने के लिए केन्द्र द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये।'
- सुनिश्चित किया जायेगा कि पन्द्रहवीं लोकसभा में लोकसभा एवं राज्य विधायिकाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का विधेयक पास करवाया जाये तथा सोलहवीं लोकसभा के चुनाव महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के आधार पर हों। इसका क्या हुआ?
- कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि देश की कम से कम आधी ग्रामीण महिलाओं को सदस्य के रूप में स्वयं-सहायता समूहों से जोड़ा जाये जो बैंकों से जुड़े हों और उनको बैंकों से सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। 50 प्रतिशत जनसंख्या की तो बात भूल जायें, 10 प्रतिशत को भी स्वयं-सहायता समूहों से नहीं जोड़ा गया है।
- विपरीत लिंग अनुपात सही करने

तथा लड़कियों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की जायेंगी। इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई।

- पंचायती राज संस्थानों की तकनीकी क्षमतायें उच्चीकृत की जायेंगी। इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई।
- हम तीन साल के भीतर सभी गांवों को ब्राडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का वादा करते हैं। कोई प्रगति नहीं हुई।
- हम सबको सामाजिक सुरक्षा, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यरक्षा का वादा करते हैं। इनमें से कुछ भी लागू नहीं हुआ।
- हम छोटे एवं मझोले उद्यमों की प्रेत के लिए लक्षित क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का वादा करते हैं। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
- स्वयंसेवी राष्ट्रीय युवा कार्पस की योजना बना कर उसे शुरू करेंगे जो 18 -23 वर्ष के युवा पुरुषों व महिलाओं को रचनात्मक राष्ट्रनिर्माण गतिविधियों में काम करने का मौका देगा और जिसके लिये उनको समुचित भुगतान किया जायेगा। इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया।
- मझोली स्तर वाली पंचायतों के मुख्यालयों पर हम ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल अदालतों के माध्यम से न्यायिक सुधार लागू करेंगे। ये सब कहां हैं?
- 100 दिनों में मुद्रास्फीति तथा मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण करेंगे। पार्टी नीत सरकार इस मामले में बुरी तरह विफल हुई है।
- सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर विदेशों में जमा काले धन वापस ले आयेंगे। इस मुद्दे पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार सरकार की खिंचाई की है। लेकिन अब भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
- हर साल दो करोड़ रोजगारों का सृजन करेंगे। इसके उलट लोगों की नौकरियां जाती रहीं।
- हम सामाजिक सद्भावना, युवा रोजगार, ग्रामीण विकास आर्थिक नवोत्थान, महिला सशक्तिकरण एवं समान अवसर लायेंगे। 2004 के इन 6 पैकेजों को भुला दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2012-13 में योजनागत खर्च में 75,000 करोड़ तथा वित्त वर्ष 2011-12 में एक लाख करोड़ की कमी करेंगे। यह नहीं किया गया।

कांग्रेस-नीत सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है और इसके कुप्रबंधन के कारण आज देश अव्यवस्था का अनुभव कर रहा है। नीतिगत विकलांगता के कारण प्रशासन, व्यापार, नैतिकता एवं विश्वास का पतन हुआ है और यह कांग्रेस के एक दशक तक चले कुशासन का परिणाम हैं।

राजग ने 2004 में संप्रग को शानदार अर्थव्यवस्था सौंपी थी जो 8.4 प्रतिशत की दर से प्रगति कर रही थी। आज यह दर फिसल कर 4.6 प्रतिशत पर आ गयी है। राजग ने उचित प्रबंधन द्वारा मुद्रास्फीति की दर को एक अंक तक रखने में सफलता पायी थी। संप्रग सरकार के कुप्रबंधन ने इसे दो अंकों तक पहुंचा दिया है। संप्रग सरकार के अंतर्गत एक समय यह 18 से 20 प्रतिशत तक पहुंच गया था। सारे मैक्रो आर्थिक संकेतक, जैसे राजकोषीय घाटा, व्यापार घाटा और मुद्रास्फीति सामान्य की तुलना में बहुत ऊंचे रहे। इसके परिणामस्वरूप रुपये की कीमत में काफी गिरावट आयी। राजग सरकार में डालर की विनिमय दर 40 से 42 थी। संप्रग शासन में यह 60 से ऊपर पहुंच गयी और एक समय तो 70 रुपये प्रति डालर तक पहुंच गयी थी।

राजग अपने 6 वर्ष के शासनकाल में 6.7 करोड़ रोजगार सृजित करने में सफल हुई थी, पर संप्रग अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 1.54 करोड़ रोजगार ही सृजित कर सकी। अब कांग्रेस 10 करोड़ नये रोजगारों का वादा कर रही है। सजग सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग तेजी से बनाये। पिछले 32 वर्ष में बने राजमार्गों के 50 प्रतिशत का निर्माण श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ। संप्रग सरकार ने स्वयं यह बात सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार की। राजग ने पांच वर्ष के कार्यकाल में 23,814 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कराया। संप्रग सरकार राजग सरकार की इस पहल को आगे बढ़ाने में पूरी तरह विफल रही।

केवल कानून बनाना ही काफी नहीं होता है। वास्तव में बिल के बजाय राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है जो कांग्रेस के पास नहीं है। पिछले तीन वर्षों से शिक्षा का अधिकार केवल कागजों पर बना हुआ है। भोजन का अधिकार, यानी खाद्य सुरक्षा केवल वोट सुरक्षा के लिए है। कांग्रेस 10 वर्षों तक इस मामले पर खामोश रही और केवल चुनावों के पहले यह विधेयक लायी। इसने शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च का वादा किया था, पर यह पिछले 10 वर्षों में चार प्रतिशत भी आबंटित नहीं कर पायी। इसने स्वास्थ्य

शेष पृष्ठ 26 पर

कांग्रेस की बेबसी

बलबीर पुंज

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी के जवाब में हाल में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस समय सरकार के पास विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन का कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। वहीं विदेशी टैक्स पनाहगाहों में जमा काले धन को लेकर कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के रवैये पर सर्वोच्च अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पिछले दिनों कहा है कि कालेधन की वापसी के लिए आपने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने के अलावा कुछ नहीं किया। अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए बताया कि यदि काला धन वापस आ जाए तो अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी और हम लोग जो टैक्स देते हैं उनमें 30 प्रतिशत की कमी आएगी।

काले धन को लेकर कांग्रेस की बेबसी क्या है? विदेशों में जमा काले धन की वापसी को लेकर कांग्रेस प्रारंभ से ही ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मुद्दे को गंभीरता से उठाती आई है वहीं कांग्रेस इसकी गंभीरता को कमतर साबित करने की कोशिश करती रही है। इस बार के कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में काले धन पर विशेष दूत की नियुक्ति का वादा किया गया है। निरंतर हो रही आलोचना के कारण कांग्रेस इस बार काले धन को लेकर गंभीर होने का दिखावा कर रही है, किंतु काले धन की वापसी को लेकर कांग्रेस का रवैया अब तक जुबानी जमाखर्च का ही रहा है।

वस्तुत: 4 जुलाई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने काले धन की वापसी और जांच की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए एसआइटी गठित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति को तुरंत एसआइटी से जुड़ने का भी आदेश दिया था। एसआइटी को सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करना था। एसआइटी स्वीकार करने में सरकार द्वारा दिखाई जा रही अनिच्छा पर आपत्ति व्यक्त करते हुए जस्टिस एचएल दत्तू की अगुवाई वाली बेंच ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकार के पास पहले से मौजूद मैकेनिज्म होने के कारण एसआइटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कांग्रेस को काले धन का मुद्दा गर्माने पर बोफोर्स का भूत फिर से सामने आने का खौफ सताता है। बोफोर्स दलाली में लूटी गई रकम स्विस बैंक में जमा थी। बोफोर्स दलाली में क्वात्रोची को 64 करोड़ का कमीशन मिला था। वाजपेयी के कार्यकाल में ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क कर इन खातों से धन निकालने पर रोक लगवाई गई थी, किंतु संप्रग के कार्यकाल में वह रोक हटवा दी गई, जिसके कारण क्वात्रोची दलाली का सारा धन निकाल पाने में सफल हुआ।

कालेधन और टैक्स हेवेंस को खत्म करने के लिए चल रहे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने अप्रैल, 2007 में ही डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर भारत के संबध में समुचित कदम उठाने की अपील की थी। तत्कालीन वित्तमंत्री की ओर से जो जवाब आया उससे सरकार द्वारा कदम उठाने का संकेत मिला था। किंतु धन वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ करने की जगह सरकार ने जर्मनी स्थित भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया कि स्विस बैंकों में काला धन रखने वाले भारतीयों का नाम उजागर

काले धन को लेकर कांग्रेस की बेबसी क्या है? विदेशों में जमा काले धन की वापसी को लेकर कांग्रेस प्रारंभ से ही ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मुद्दे को गंभीरता से उठाती आई है वहीं कांग्रेस इसकी गंभीरता को कमतर साबित करने की कोशिश करती रही है। इस बार के कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में काले धन पर विशेष दूत की नियुक्ति का वादा किया गया है। निरंतर हो रही आलोचना के कारण कांग्रेस इस बार काले धन को लेकर गंभीर होने का दिखावा कर रही है, किंतु काले धन की वापसी को लेकर कांग्रेस का रवैया अब तक जुबानी जमाखर्च का ही रहा है।

करने के लिए जर्मनी सरकार पर दबाव नहीं डाला जाए। कांग्रेस आखिर किन चेहरों को बचाना चाहती है?

अमेरिका स्थित 'ग्लोबल फाइनेंसियल इंटेग्रिटी' के अनुमान के अनुसार भारत से प्रतिवर्ष 27 अरब डॉलर स्विस बैंक आदि में जमा कराया जाता है। 160 विकासशील देशों की सूची में भारत का स्थान पांचवां है। जीएफआइ के अनुसार 2002 से 2006 के बीच भारत से औसतन 22.7 अरब से 27.3 अरब डॉलर प्रतिवर्ष कालाधन विदेशी बैंकों में जमा होता रहा। 'आर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनोमिक कार्पोरेशन एंड डेवलपमेंट' ने अप्रैल 2009 के शुरू में प्रकाशित लेखा-जोखा में उल्लेख किया था कि स्विस बैंकों समेत अन्य टैक्स हेवेंस में 25 लाख करोड़ से लेकर 70 लाख करोड़ की धनराशि है। जर्मनी के वित्त मंत्रालय ने एलटीजी बैंक से जो सूची प्राप्त की है उसमें करीब 100 भारतीयों के भी नाम शामिल हैं। कांग्रेस इन कर चोरों के नाम उजागर क्यों नहीं करती?

स्विट्जरलैंड की प्रमुख पत्रिका 'स्विजर इलस्त्रीएते' ने 19 नवंबर, 1991 के अपने अंक में राजीव गांधी समेत तीसरी दुनिया के करीब दर्जन भर राजनेताओं के नामों का खुलासा किया था, जिन्होंने स्विस बैंकों में अपनी काली कमाई जमा कराई थी। केजीबी दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए पत्रिका ने लिखा था कि राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी अपने अवयस्क पुत्र के नाम पर उन गोपनीय खातों की देखरेख कर रही हैं, जिनमें 2.5 अरब स्विस फ्रैंक जमा हैं। इसके आलोक में 7 दिसंबर, 1991 को संसद में सीपीआइ-एम के सांसद अमल दत्ता ने नाम लेकर 2.2 अरब डॉलर का मामला उठाया था।

दूसरा खुलासा रूसी खुफिया एजेंसी-केजीबी के गोपनीय दस्तावेजों से हुआ था। येवजेनिया अल्बाट्स नामक एक खोजी पत्रकार ने अपनी पुस्तक-'दि केजीबी एंड इट्स होल्ड इन रशिया' पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर' में इन दस्तावेजों के आधार पर गंभीर खुलासा किया है। अल्बाट्स ने उपरोक्त पुस्तक की पृष्ठ संख्या 223 में लिखा है, 'केजीबी' प्रमुख विक्टर चेबरीकोव के हस्ताक्षर वाले एक पत्र में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के पुत्र के साथ केजीबी के रिश्तों की बात दर्ज है। इसमें सोवियत व्यापार संघों के सहयोग से अपने नियंत्रण वाली फर्म को हो रहे व्यापारिक लाभ के लिए आर गांधी द्वारा आभार प्रकट करने का भी उल्लेख है। अल्बाट्स ने यह भी खुलासा किया है कि सन् 2005 में केजीबी प्रमुख विक्टर चेबरीकोव ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति से राजीव गांधी के परिजनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पाओला मैनो (सोनिया गांधी की मां) को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने की अधिकारिता देने को कहा था।

अल्बाट्स के खुलासे से भी पहले रूसी मीडिया ने दलाली का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। उन खुलासों के आधार पर अंग्रेजी समाचार पत्र 'द हिंदू' ने 4 जुलाई, 1992 के अपने संस्करण में लिखा था, ''रूसी विदेशी खुफिया सेवा इस संभावना को स्वीकार करती है कि राजीव गांधी के परिवार की नियंत्रण वाली कंपनी को मुनाफे वाले सोवियत ठेके दिलाने में केजीबी ने मदद की होगी।''

क्या ये सभी आरोप गंभीर नहीं हैं? क्या ये मामले भारत के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की प्रामाणिकता पर उंगली नहीं उठाते? यदि ये आरोप निराधार हैं तो इन आरोपों का अब तक खंडन क्यों नहीं किया गया? सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने आज तक इन पत्र-पत्रिकाओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? कहीं इस खामोशी में छिपा राज ही काले धन की वापसी में अवरोध तो नहीं खड़ा कर रहा? ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

(साभार- दै. जागरण)

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

पृष्ठ 24 का शेष...

पर जीडीपी के 2 से 3 प्रतिशत खर्च का वादा किया था, पर यह इस मद पर जीडीपी का केवल 1.3 प्रतिशत ही आवंटित कर पायी। संप्रग सरकार के शासनकाल में सैकड़ों फैक्ट्रियां बीमार हुई और लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गये।

कांग्रेस द्वारा जनता से किये अपने वादे पूरे न करने से जनता में भारी गुस्सा व्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप जनता में स्पष्ट इच्छा बन रही है कि केन्द्र में भाजपा-नीत सरकार बनायी जाये। श्री मोदी को जमीनी स्तर पर भारी समर्थन दिखायी पड़ रहा है जो देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकते हैं तथा राष्ट्र को प्रगति एवं समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकते हैं।■

(साभार- पायनियर)
~~~~~~~~~~

कांग्रेस का सेक्युलर विलाप

✍ हृदयनारायण दीक्षित

बुरे मन से जीत नहीं मिलती। कांग्रेस पराजित मनोव्यथा में है। वह बिना लड़े ही हार गई है। राष्ट्रीय स्वाभिमान सुशासन और विकास का कोई विकल्प नहीं होता। नरेंद्र मोदी इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार बनाने के दावेदार हैं, लेकिन सोनिया गांधी का ताजा मुद्दा 'पंथनिरपेक्षता' है। उन्होंने जामा मस्जिद के इमाम सैय्यद अहमद बुखारी के नेतृत्व में आए मुस्लिमों के सामने राजनीति में आने का राज खोला- राजनीति में आने की शुरुआती हिचकिचाहट थी, लेकिन पंथनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए वह राजनीति में आई। पंथनिरपेक्षता की मजबूती का सोनिया दृष्टिकोण दयनीय और हास्यास्पद है। कहां मजहबी इमाम और कहां पंथनिरपेक्षता? दिलचस्प यह है कि दोनों मिलकर पंथनिरपेक्ष वोट का विभाजन रोकेंगे। आखिरकार ये पंथनिरपेक्ष वोट क्या हैं? क्या इमाम से जुड़े मजहबी लोग ही पंथनिरपेक्ष हैं? क्या गैरमुस्लिम मतदाता पंथनिरपेक्ष नहीं हैं? क्या राष्ट्रीय विकास और सुशासन अब कोई मुद्दा नहीं हैं? सोनिया की अपील सांप्रदायिक है। एके एंटनी ने मोदी को राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया है। वह मोदी को रोकने के लिए सभी दलों का समर्थन लेने के लिए बेताब हैं। मोदी ही खतरा हैं और वही कथित पंथनिरपेक्ष दलतंत्र की बेचैनी। वामदल, सपा और बसपा भी मोदी को ही मुद्दा बना रहे हैं।

क्या पंथनिरपेक्षता को वाकई कोई खतरा है? संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले दल भी बहुधा ऐसी ही बातें करते थे। वह सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के लिए ही समर्थन का औचित्य बताते थे। उनके अनुसार कांग्रेस और वे ही पंथनिरपेक्ष थे और भाजपा सांप्रदायिक। उन्होंने नरेंद्र मोदी को खतरनाक सांप्रदायिक बताया। मोदी ने सैकड़ों रैलियां कीं। कहीं भी सांप्रदायिक प्रश्न नहीं उठाए। उन्होंने 'राष्ट्र सर्वोपरिता' को सर्वोच्च मंत्र बताया। राष्ट्रभक्ति सांप्रदायिक नहीं होती। गांधीजी विश्व मानव थे, लेकिन राष्ट्रभक्ति से सराबोर थे। राष्ट्र सर्वोपरिता और पंथनिरपेक्षता में कोई टकराव नहीं। भेदभाव से रहित राष्ट्रीय विकास में सबकी समृद्धि है। भेदभाव रहित सुशासन में सबको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी है। मोदी यही मुद्दे लेकर जीत के करीब हैं, लेकिन कांग्रेस को पंथनिरपेक्षता पर खतरा नजर आ रहा है। यदि ऐसा कोई खतरा है तो खतरा-खतरा चिल्लाने वाले दल और नेता एक क्यों नहीं हो जाते? मुलायम सिंह ने पहल की है। उन्होंने सोनिया राहुल के विरुद्ध उम्मीदवार नहीं उतारा।

बहरूपिया है पंथनिरपेक्षता। संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका में 'पंथनिरपेक्षता' को महत्व नहीं दिया। सेक्युलरवाद भारतीय विचार नहीं था। यह संगठित ईसाई चर्च और राज्यव्यवस्था के टकराव से पैदा हुआ। भारत में विदेशी सेक्युलरवाद की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी को इसकी जरूरत महसूस हुई। 1975 के जेपी आंदोलन ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने आपतकाल लगाया। संपूर्ण विपक्ष जेल में था। संविधान संशोधन हुआ। संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथनिरपेक्षता का अर्थ भौतिक या इहलौकिक होता है। राजनीति में इसका अर्थ मजहबी वरीयता हो गया। संविधान के अधिकृत

कांग्रेस पराजित मनोव्यथा में है। वह बिना लड़े ही हार गई है। राष्ट्रीय स्वाभिमान सुशासन और विकास का कोई विकल्प नहीं होता। नरेंद्र मोदी इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार बनाने के दावेदार हैं, लेकिन सोनिया गांधी का ताजा मुद्दा 'पंथनिरपेक्षता' है। उन्होंने जामा मस्जिद के इमाम सैय्यद अहमद बुखारी के नेतृत्व में आए मुस्लिमों के सामने राजनीति में आने का राज खोला- राजनीति में आने की शुरुआती हिचकिचाहट थी, लेकिन पंथनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए वह राजनीति में आई। पंथनिरपेक्षता की मजबूती का सोनिया दृष्टिकोण दयनीय और हास्यास्पद है।

हिंदी पाठ में इसका अर्थ पंथनिरपेक्षता है। वोट बैंक राजनीति ने 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द चलाया, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में इसका मतलब मजहब खास को पुरस्कार और बाकी का तिरस्कार है।

आस्था, विश्वास और सेक्युलरवाद परस्पर विरोधी हैं। पंथिक आस्थालु असांप्रदायिक नहीं होते। वे अपने संप्रदाय के पंथिक प्रवक्ता होते हैं। अचरज है कि सोनिया गांधी की पंथनिरपेक्षता को इमाम बुखारी मजबूती देंगे? लेकिन कांग्रेस के लिए यह नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी इन्हीं अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी से कथित सेक्युलरवाद के नाम पर मजहबी वोट लेने का समझौता किया था। असल में पंथनिरपेक्षता कोई मूलभूत प्रश्न नहीं है और न ही यह कांग्रेस या अन्य कथित सेक्युलर दलों की कोई निष्ठा ही है? सारा मामला मजहबी वोट बैंक साधने का है। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली आदि की राजव्यवस्थाओं ने सेक्युलरवाद का सदुपयोग किया था। उन्होंने सेक्युलरवाद लाकर पोप और चर्च के दबावों से मुक्ति का उपाय निकाला। लेकिन भारतीय राजनीति सेक्युलर आवरण में मजहबी वोट बैंक को मजबूत करने और राष्ट्रीय एकता तोड़ने का काम कर रही है। उसे इस वोट बैंक को डराने के लिए एक खलनायक की दरकार थी। वह मोदी को पंथनिरपेक्षता का शत्रु सिद्ध करना चाहती है, लेकिन मोदी अपने अभियान में भारतीय जनता की बुनियादी समस्याओं को ही महत्व दे रहे हैं।

सुशासन और राष्ट्रीय स्वाभिमान स्वाभाविक अभिलाषाएं हैं। खेती, किसानी, औद्योगिक विकास, विधि के समक्ष समता, सबको शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाएं चुनावी मुद्दा हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार दस वर्षीय संप्रग सरकार के कारण मुद्दा बने हैं। सांप्रदायिक आधार पर बजट या मजहबी आरक्षण का विलाप अलगाववाद है। राज्य संरक्षित और राज्य अनुदानित सांप्रदायिकता बड़े मुद्दे हैं। पंथनिरपेक्षता कोई मुद्दा नहीं है। सोनिया गांधी, एंटनी और अन्य ऐसे ही नेता चुनावी बहस की दिशा बदलने को बेताब हैं। संप्रग के पास बताने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं हैं। सुशासन वह दे नहीं पाया। किसानों ने आत्महत्या की। गरीबी बढ़ी। भ्रष्टाचार संस्थागत हुआ। भ्रष्टाचार के सारे मामलों पर कोर्ट ने ही कार्रवाई की। पाकिस्तान युद्धरत है और चीन आक्रामक। विदेश नीति के मोर्चे पर भी किरकिरी हुई। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हुआ। प्रधानमंत्री के पद और प्राधिकार भी धूल में मिल गए। खार खाई जनता के बीच भाजपा का जनअभियान कामयाब हो गया। कांग्रेस जीर्ण-शीर्ण, रुग्ण और मनोबल हीन हुई। सो अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एकमात्र सहारा है।

अब बेमतलब है सेक्युलर विलाप। कांग्रेसी बयानों में अंतर्विरोध हैं। वे कहते हैं कि मोदी नहीं जीतेंगे। फिर कहते हैं कि मोदी की कोई हवा नहीं है। फिर कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए सभी सेक्युलरों को एक हो जाना चाहिए। मोदी ही विषय हैं और मोदी ही मुद्दा। बाकी दल भी मोदी की ही सूचनाएं देते हैं- मोदी आएंगे तो दंगे बढ़ेंगे। मोदी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हैं, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वे बताते हैं कि मोदी सरकार नहीं चला सकते। कुछेक नेता दिलचस्प सूचनाएं भी दे रहे हैं- मोदी भाजपा से बड़े हो गए हैं। जितने दल, मोदी पर उससे भी ज्यादा प्रवचन। मूलभूत प्रश्न है कि चुनाव में ये कथित सेक्युलर जनता के बुनियादी सवाल क्यों नहीं उठाते? नरेंद्र मोदी ही उनके विवेचन और विश्लेषण का मुख्य मुद्दा क्यों हैं? साफ जाहिर है कि मोदी का जादू ही सबके सिर पर सवार है। सोनिया गांधी ने इसी जादू की दवा खोजी है- पंथनिरपेक्षता, लेकिन यह एक्सपाइरी डेट वाली दवा है। सारे दल नोट करें कि भारतीय जनगणमन को राष्ट्रीय विकास चाहिए, सुशासन और समृद्धि चाहिए और चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान। जो ऐसा दे सकते हैं, कर सकते हैं वे अपने शपथपत्र के साथ मतदाताओं के बीच आएं और जनप्रश्नों से मुठभेड़ करें। कृपया मूल मुद्दों से भटकाव का प्रयास न करें। ■

(लेखक उप्र विधानपरिषद के सदस्य हैं)

(साभार- दै. जागरण)

मूलभूत प्रश्न है कि चुनाव में ये कथित सेक्युलर जनता के बुनियादी सवाल क्यों नहीं उठाते? नरेंद्र मोदी ही उनके विवेचन और विश्लेषण का मुख्य मुद्दा क्यों हैं? साफ जाहिर है कि मोदी का जादू ही सबके सिर पर सवार है। सोनिया गांधी ने इसी जादू की दवा खोजी है- पंथनिरपेक्षता, लेकिन यह एक्सपाइरी डेट वाली दवा है। सारे दल नोट करें कि भारतीय जनगणमन को राष्ट्रीय विकास चाहिए, सुशासन और समृद्धि चाहिए और चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान।

सुनामी बन रही है मोदी की लहर

✍ कंचन गुप्ता

भले ही जनमत सर्वेक्षण यह अनुमान ठीक लगाने के उपयुक्त न हों कि प्रत्येक प्रमुख पार्टियों को चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी और वह भी आम चुनाव में जो एक महीने से ज्यादा समय तक चलने वाला हो, लेकिन वे जनता की सोच भांपने के लिए काफी होते हैं। विभिन्न क्लाइंटों द्वारा विभिन्न एजेंसियों द्वारा करवाये हालिया दौर के जनमत सर्वेक्षणों से उसी बात की पुष्टि होती है जो बहुत लंबे समय से इस गर्मियों के चुनाव में बहस का विषय बनी हुई थी। नरेन्द्र मोदी इस दौड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि दूसरे उनसे बहुत पीछे हैं। इससे भाजपा की सीटों की संख्या बहुचर्चित 220 की संख्या से बहुत ज्यादा आगे निकल सकती है। यह सच है कि 7 अप्रैल को मतदान के पहले चरण से मध्य मई में होने वाले अन्तिम चरण तक बहुत कुछ बदल सकता है, हालांकि अतीत में उल्लेखनीय रूप से 2004 में चीजें असाधारण रूप से बदली थीं जब जनमत सर्वेक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले सजग की भारी विजय की भविष्यवाणी कर रहे थे, पर भाजपा हार गयी थी और सत्ता कांग्रेस के हाथों में आ गयी थी। एक दशक बाद इसका उल्टा हो सकता है।

भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को इतना भारी समर्थन मिल रहा है कि यह संकेत करना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नमो की लहर सुनामी में बदल गयी है। सोशल मीडिया इस आश्चर्यजनक परिघटना को सुनामी नाम दे रहा है और इससे गुजरात के चायवाले का विरोध करने वालों का पूरी तरह सफाया होने का खतरा पैदा हो गया है।

यह भविष्यवाणी सच हो सकती है और हम 1977 का पुनः प्रस्तुतीकरण देख सकते हैं जब उस असाधारण चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लगभग सभी लोग जीत गये थे। वे भारी कांग्रेस-विरोधी और इन्दिरा-विरोधी लहर के शिखर पर चढ़ कर वहां तक पहुंचे थे। इस बार वे मोदी की लहर पर सवार होकर ऐस ही विजय प्राप्त कर सकते हैं।

जो लोग पिछले दशक में मोदी को गालियां देकर, उनको बदनाम कर और उनका दर्जा गिरा कर एक ऐसे राजनेता का उभार रोकने का प्रयास कर रहे थे जैसा नेता भारत ने कभी नहीं देखा था, आज वे भारी परेशानी के साथ ऐसे तिनकों की तलाश में हैं जिनके सहारे वे किसी तरह तैर सकें। अब यह मोदी को दिल्ली तक पहुंचने से रोकने का संघर्ष न होकर उनके अपने बचे रहने का संघर्ष बन गया है। यदि उनको जीवित रखने वाला दिल्ली दरबार ढह गया तो उनकी जीवन रेखा ही समाप्त हो जायेगी। दिल्ली के विशिष्ट लोगों, फर्जी वामपंथी टिप्पणीकारों और फर्जी उदार बुद्धिजीवियों को यह भय भयंकर रूप से सता रहा है कि यदि वे केवल महत्वहीन ही न होंगे, बल्कि लूटियनों की दिल्ली में मुफ्तखोरों के भोजन से वंचित हो जायेंगे। यह भय अपरिवर्तनीय रूप से और जल्दी से सच होने जा रहा है। यह अत्यन्त भयंकर दुःस्वप्न है जो उनकी कल्पनाओं से परे है।

जो लोग पिछले दशक में मोदी को गालियां देकर, उनको बदनाम कर और उनका दर्जा गिरा कर एक ऐसे राजनेता का उभार रोकने का प्रयास कर रहे थे जैसा नेता भारत ने कभी नहीं देखा था, आज वे भारी परेशानी के साथ ऐसे तिनकों की तलाश में हैं जिनके सहारे वे किसी तरह तैर सकें। अब यह मोदी को दिल्ली तक पहुंचने से रोकने का संघर्ष न होकर उनके अपने बचे रहने का संघर्ष बन गया है। यदि उनको जीवित रखने वाला दिल्ली दरबार ढह गया तो उनकी जीवन रेखा ही समाप्त हो जायेगी। दिल्ली के विशिष्ट लोगों, फर्जी वामपंथी टिप्पणीकारों और फर्जी उदार बुद्धिजीवियों को यह भय भयंकर रूप से सता रहा है कि यदि वे केवल महत्वहीन ही न होंगे, बल्कि लूटियनों की दिल्ली में मुफ्तखोरों के भोजन से वंचित हो जायेंगे।

कांग्रेस तथा उनके भुगतान पर जीवित रहने वालों की गणित भयंकर रूप से गड़बड़ा गयी है। इनमें से बहुत से स्वयं को पत्रकार तथा चौबीसों घंटे व सातों दिन चलने वाले खबरिया चैनलों के संपादक की तरह और अक्सर स्वयं को विचारकों और थिंक टैंकों की तरह पेश करते हैं। इनमें से एक स्वयं को भारत के सर्वाधिक विख्यात इतिहासकार की तरह पेश करते हैं। ये

सभी ओपएड लेखक अपने द्वारा पेश विचारों को गलती से भारतीय जनता की राय मानते हैं, जबकि वास्तव में उनकी यह सोच पूरी तरह भ्रामक है।

उन्होंने हिसाब लगाया था कि यह चुनाव सेक्यूलरिज्म पर जनमत संग्रह होगा और उन्होंने भारत का विचार सामने रख कर तथा उसे खतरा बता कर मोदी को हराने की योजना बनायी थी। उनको उम्मीद थी कि लंबे समय से चली आ रही यह सोच मतदाताओं को प्रेरित करेगी और वे सांप्रदायिक भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए भ्रष्ट कांग्रेस को सत्ता में बनाये रखेंगे। निश्चित रूप से उनकी गणित भयंकर रूप से गलत थी। उन्होंने भारी गलती करते हुए 2014 की चुनाव रणनीति को स्कूल आडीटोरियम की ऐसी बहस समझ लिया था जो नेहरूवादी सेक्यूलरिज्म के लाभों पर थी। लेकिन कांग्रेस अभी दौड़ शुरू करने का प्रयास कर रही है जबकि मोदी उछलते हुए विजय रेखा के पास पहुंच गये हैं और विजेता के स्टैंड पर खड़े होने की तैयार कर रहे हैं।

सामान्य समझदारी के अनुसार कांग्रेस और उसके मनपसंद लोग अब भी अपनी रणनीति पुन: निर्धारित कर नयी तरकीबें अपना सकते हैं जो भले ही मोदी को विजयी होने से न रोक सकें, पर उनको सारे मैडल झपटने से वंचित कर दें। इसके बजाय हमें एक पुनर्जीवित प्रयास नजर आ रहा है जिसमें सेक्युलर कम्युनल बहस को चुनाव अभियान के मुख्य केन्द्र में लाने के प्रयास हो रहे हैं। हालांकि, ये प्रयास अप्रत्याशित नहीं हैं, पर कोई भी इनसे प्रभावित नहीं है। यह चुनाव इस निर्धारण के लिए नहीं हैं कि कौन ज्यादा सेक्युलर या ज्यादा कम्युनल है, बल्कि इस बात के लिए है कि कौन नौकरियां दे सकता है और थाली में भोजन सुनिश्चित कर सकता है। दीवाल की लिखावट बता रही है कि मामला अर्थशास्त्र का है और कांग्रेस जो समझ रही है उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

एक प्रकार से यदि मोदी चुनावों में भारी विजय प्राप्त करने में सफल होते हैं तो वे भारत के विचार को पुन: परिभाषित करेंगे और वैसे भी अब मोदी की विजय पूर्व निर्धारित परिणाम मानी जा रही है। मोदी भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां विकास, प्रगति एवं समृद्धि के नये मूल्य हों तथा उनको फर्जी समाजवाद और धोखाधड़ी भरे सेक्युलरिज्म पर वरीयता मिले।

इस प्रकार हमारे सामने वह दृश्य आता है जब सोनिया गांधी जमीन पर कब्जा करने वाले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम से मिल रही हैं, जबकि उनको हफ्ता वसूल करने वाले और रैकेटियर माना जाता है जिनका आश्चर्यजनक प्रभाव पुरानी दिल्ली की सीमाओं से बाहर कहीं नहीं है। इसके बाहर मुस्लिम वोटों के सौदागार का न तो प्रभाव है और न उनसे कोई डरता है। यहां तक कि जामा मस्जिद के पास रहने वाले अधिकांश लोगों में भी शायद ही कोई उनकी प्रशंसा करने वाला हो। शाही इमाम ने सोनिया गांधी को मुसलमानों से यह अपील कर अनुगृहीत किया है कि सेक्यूलर वोटों को बंटने से रोका जाये, जो अपने आप में न केवल हास्यास्पद बल्कि निन्दनीय भी है। हास्यास्पद इसलिये कि सभी मुस्लिम मतों को सेक्यूलर कहा जाता है और निन्दनीय इसलिये कि धर्म और राजनीति का घालमेल अन्तत: एक जहरीला पेय तैयार करता है।

ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी, शाही इमाम ओर सेक्यूलरवादियों की थकी-हारी सेना के पैदल सिपाही गठजोड़ बनाने के प्रयासों में अकेले हैं। वे अपने किले पर हमला रोकने का अन्तिम प्रयास कर रहे हैं। द इकोनोमिस्ट ने निरर्थक रूप से भारतीय मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया है और द गार्जियन ने भी मतदान के बारे में एक-दो सबक सिखाने की कोशिश की है। उनकी सामूहिक अपील भारत से मतदान करने के बजाय अस्वीकार करने को कहने की है। ऐसा नहीं लगता कि इस अपील का ज्यादा असर होगा। भारत के मुसलमान अब किसी सामुदायिक नर्सरी में नहीं हैं जो काल्पनिक शिकायतों की दुनिया में हो अथवा मुगल युग वापस आने की आशा कर रहे हों। इस गर्मी में पहली बार मतदान करने वाले करोड़ों लोगों में ऐसे मुस्लिम नौजवान शामिल हैं जिनकी इच्छायें हिन्दुओं, ईसाइयों और सिख नौजवानों के समान हैं। वे बेहतर जीवन चाहते हैं और बेहतर भारत चाहते हैं।

एक प्रकार से यदि मोदी चुनावों में भारी विजय प्राप्त करने में सफल होते हैं तो वे भारत के विचार को पुन: परिभाषित करेंगे और वैसे भी अब मोदी की विजय पूर्व निर्धारित परिणाम मानी जा रही है। मोदी भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां विकास, प्रगति एवं समृद्धि के नये मूल्य हों तथा उनको फर्जी समाजवाद और धोखाधड़ी भरे सेक्युलरिज्म पर वरीयता मिले। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं)

(साभार- पायनियर)